नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 256, नई दिल्ली, शनिवार 22 नवम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

संघर्ष में कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि जीवन हमें हमेशा एक और मौका देता है।

03 भारतीय मजदूर संघ ने चारों श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन का स्वागत किया:
06 समस्या बढ़ाती सुंदर दिखने की चाहत
08 27 नवंबर को लगाया जाएगा जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण कैंप – मुख्य कृषि अधिकारी

क्या माइक्रोप्लास्टिक बिगाड़ रहा दिल्ली की सेहत ?

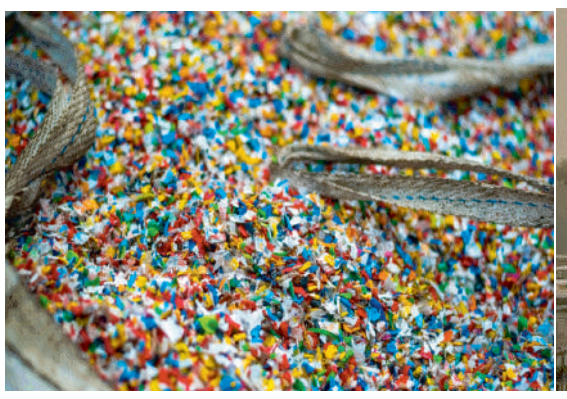

जहरीली हवा ने जहां एक ओर दिल्ली वालों की दिनचर्या बदल दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषित हवा ने बच्चों, बुजुर्गों समेत महिलाओं के समक्ष अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी कर दीं हैं।सच तो यह है कि साल दर साल राजधानी में प्रदूषण से परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि दिल्ली पिछले कई वर्षों से प्रदूषण की मार झेल रही है। यहां तक कि गर्भस्थ शिशुओं तक पर प्रदूषण का व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। इस क्रम में यदि हम जन्म पंजीकरण के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले वर्ष जन्म लेने वाले 30.31 प्रतिशत नवजात शिशुओं का वजन दो किलोग्राम तक था। वहीं, वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 31.54 प्रतिशत था। गौरतलब है कि जन्म के समय नवजात का वजन ढाई किलोग्राम से कम हो तो उसे सामान्य से कम माना जाता है। ऐसे में जन्म के समय सामान्य से कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या 30-31 प्रतिशत से अधिक है। इतना ही नहीं, एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक में छपी एक खबर के अनुसार चांदनी चौक की हवा में प्लास्टिक के कण भी पाये गये हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जैसा कि दैनिक ने लिखा है- 'चेन्नई और मुंबई की तुलना में कोलकाता और दिल्ली की आबोहवा में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी कहीं अधिक है। इस वजह से इन दोनों शहरों की हवा में प्लास्टिक के ऐसे सूक्ष्म अंश अधिक हैं, जो सांस के जरिये शरीर में पहुंच सकते हैं। इस तरह के आइएमपी (सांस के साथ शरीर में पहुंचने योग्य माइक्रो प्लास्टिक) का कोलकाता में स्तर 14.23 माइक्रोग्राम घन मीटर और दिल्ली में 14.18 माइक्रोग्राम घन मीटर पाया गया। चेन्नई और मुंबई के वातावरण में इसकी मौजूदगी बहुत कम रही।' बताता चलूं कि खराब कूड़ा प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है । वास्तव में, सर्दी के मौसम में प्रदूषण बढ़ने के साथ हवा में माइक्रो प्लास्टिक का स्तर भी 14 से 71 प्रतिशत बढ़ जाता है। दरअसल, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्दियों में कूड़े का ठीक से प्रबंधन नहीं हो पाता और लोग सिंथेटिक कपड़े ज्यादा पहनते हैं। ठंड की वजह से हवा नीचे ही अटकी रहती है, जिससे प्रदूषण ऊपर नहीं उठ पाता। इस मौसम में पैकेट वाले खाने और प्लास्टिक वाले सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जिससे प्लास्टिक कूड़ा ज्यादा बनता है। दिल्ली के चांदनी चौक और सरोजिनी नगर जैसे बाजारों में हवा में माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा पाया गया है। बहरहाल, क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि

राजधानी में 22 स्थानों पर प्रदूषण का स्तर हाल ही में 400 पार कर गया।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 19 नवंबर 2025 को बुधवार के वायु गुणवत्ता सूचकांक में 18 नवंबर 2025 मंगलवार की अपेक्षा लगभग 20 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। गौरतलब है कि मंगलवार को मानक एक्यूआई 374 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को यह 392 दर्ज किया गया। शाम 7 बजे 22 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वास्तव में,

हवा की गति कम, तापमान में गिरावट और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण राजधानी में प्रदूषण के स्तर में लगातार पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई 300 से अधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजधानी में बुधवार की सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 391 दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली में लगातार छठे दिन वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। बहरहाल, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्र लगातार शामिल होते रहे हैं। यहाँ सर्दियों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर तक पहुँच जाती है, क्योंकि वाहन धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और आसपास के राज्यों में पराली जलने का असर मिलकर प्रदूषण बढ़ा देते हैं। ठंडी हवा और कम हवा की रफ्तार प्रदूषित कणों को जमीन के पास रोके रखती है, जिससे पीएम. और पीएम का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी अक्सर 'बहुत खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच जाते हैं। इस प्रदूषण से साँस और हृदय संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं और बच्चों-बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली-एनसीआर को वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र बना दिया है। इसी क्रम में हाल ही में शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित खेल स्पर्धाएं स्थगित करने का निर्देश देने पर भी विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि एनसीआर के कई स्कूल नवंबर में भीषण वायु प्रदूषण के बीच खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब बड़े लोग एयर प्यूरीफायर चालू करके बंद जगहों पर बैठे होते हैं, तो बच्चे खुले 'गैस चैंबर' में खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश गवई ने सीएक्यूएम से कहा, स्कूलों में खेल गतिविधियों को सुरक्षित महीनों में आयोजित कराने पर विचार करने को कहा। बहरहाल, सरल शब्दों में कहें तो हर साल ठंड शुरू होते ही विशेषकर नवंबर , दिसंबर और जनवरी के महीनों में दिल्ली-एनसीआर की हवा इतनी खराब हो जाती है कि लोगों का स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार बढ़ती इस समस्या को रोकने के लिए प्रभावी व कारगर कदम उठाने के बजाय अलग-अलग स्तर पर लापरवाही दिखाई देती है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है।ऐसे समय में यह चाहिए कि स्कूल-कालेज बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खेलकूद या बाहरी गतिविधियों के लिए साफ-सुथरे नियम बनाएं, ताकि बच्चे जहरीली हवा से बच सकें। मगर अक्सर होता यह है कि कार्यक्रम बनाते समय प्रदूषण के खतरे को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे बच्चों की सेहत पर और ज्यादा असर पड़ता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि बच्चों के लिए बाहर खेलना भी खतरे से भरा हो जाता है। इसके बावजूद कई बार स्कूल और अधिकारी खेल गतिविधियों की योजना बनाते समय इस स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं।इसी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि वह नवंबर-दिसंबर में होने वाली स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएँ सुरक्षित महीनों तक टालने पर विचार करे। इसके बाद आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी(उत्तर प्रदेश) जैसे राज्यों को यह सलाह दी है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इस दौरान होने वाली शारीरिक और खेल गतिविधियाँ स्थगित की जाएँ, जैसा कि सर्दियों में धुंध, ठंड और प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली-एनसीआर की हवा कई बार गैस चेंबर जैसी हो जाती है और साफ हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वास्तव में, दिल्ली और दिल्ली-एनसीआर में हाल के महीनों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। कई इलाकों में एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) अक्सर 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है, जबकि कुछ स्थानों पर यह 400 से ऊपर पहुंचकर 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गया। मीडिया में उपलब्ध खबरों से जानकारी मिलती है कि दिवाली और ठंड की शुरुआत के दौरान प्रदूषण और तेजी से बढ़ गया, जिससे पीएम 2.5 जैसे खतरनाक कणों का स्तर राष्ट्रीय मानकों से दो से तीन गुना तक अधिक पाया गया। वातावरण में इन सूक्ष्म कणों की मौजूदगी आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों पर या यूं कहें कि हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। दिल्ली-एनसीआर के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने लगातार कई दिनों तक खराब-से-अत्यधिक खराब हवा दर्ज की, जो बताता है कि सुधार की कोशिशों के बावजूद हालात स्थिर नहीं हो पा रहे। हालांकि, साल के कुछ महीनों में औसत एक्यूआइ में मामूली सुधार देखने को मिला, लेकिन सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता फिर तेज़ी से गिर जाती है। कुल मिलाकर, यह स्थिति शहर के बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करती है और साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए लगातार, सख्त और समन्वित प्रयासों की जरूरत को रेखांकित करती है। निष्कर्षतः, यह बात कही जा सकती है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। अदालतों की सख्त टिप्पणियों के बावजूद स्कूलों में खेल गतिविधियाँ न रोकना स्पष्ट लापरवाही है। सर्दियों में जब कई शहरों की हवा 'गंभीर' स्तर पर पहुँच जाती है, तब एकरूप और कड़ी नीति लागू करना ही इस समस्या से निपटने का व्यावहारिक समाधान है। वास्तव में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि कोयला, डीज़ल और पेट्रोल से होने वाले उत्सर्जन में कमी आए। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर लोगों को निजी वाहनों की जगह बस, मेट्रो और साझा यातायात का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तीसरा प्रभावी उपाय औद्योगिक इकाइयों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाना है, जिससे धुआं और हानिकारक गैसों को फिल्टर करके ही हवा में छोड़ा जा सके। चौथा, हरित क्षेत्र और पेड़-पौधों की संख्या बढ़ाना हवा की गुणवत्ता सुधारने में बेहद सहायक है, क्योंकि ये प्रदूषक कणों को सोख लेते हैं। अंत में, कचरा प्रबंधन और पराली जलाने पर सख्त नियंत्रण व जागरूकता जरूरी है, ताकि धुएं और जहरीले कणों के फैलाव को रोका जा सके।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

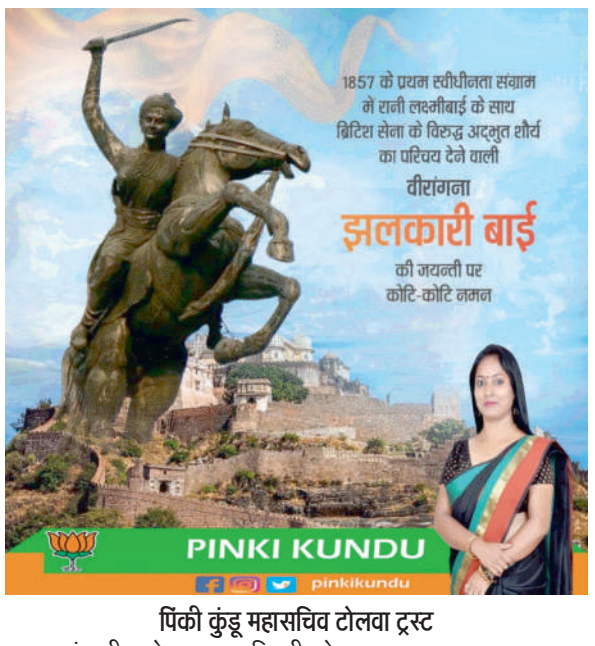

पिंकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश

वीरांगना झलकारी बाई जयंती पर विनम्र नमन
स्वाधीनता संग्राम की अदम्य योद्धा और दुर्गा दल की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई जी की जयंती पर कृतज्ञ श्रद्धांजलि।
मातृभूमि के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका अद्वितीय साहस, नेतृत्व और बलिदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।
उनकी वीरगाथा भारतीय इतिहास का गौरव है और हर पीढ़ी को राष्ट्रहित में दृढ़ता, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देती है।

पिंकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश

ज़िंदगी में एक दर्द ऐसा है जो न दिखता है, न किसी को पता चलता है। पर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है।

वह है हीनभावना।

वो एहसास कि मैं दूसरों से कम हूँ। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं कर पाया ? कहीं लोग मुझे बेकार न समझ लें

ये डर, ये तुलना, धीरे-धीरे हमारी हिम्मत खा जाती है।

हम वही काम नहीं कर पाते जिन्हें करने के लिए हमारी आत्मा पुकारती है। हम वही जगहों से बचते हैं जहाँ हमें जाना चाहिए था। हम वही लोग बन जाते हैं, जिन्हें खुद से नज़रें मिलाने में भी डर लगता है।

हीनभावना हमें दुनिया से नहीं, खुद से दूर कर देती है।

अब सुनिए किस्सा हनुमान जी और उनकी हीनभावना का ।

हाँ, वही हनुमानजी जिनकी शक्ति असीम, जिनका साहस अनुपम और जिनकी बुद्धि अतुलनीय थी।

पर क्या आप जानते हैं ? लंका जाने से पहले, हनुमानजी स्वयं को छोटा समझते थे।

उन्हें अपने सामर्थ्य का पता ही नहीं था ।उन्हें लगता था कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊँगा। मुझमें क्या विशेष है ?

और तभी जामवंतजी ने उन्हें याद दिलाया—

हे पवनपुत्र ! तुम स्वयं को कम आँकते हो, पर तुम्हारी शक्ति तो समुद्रों को लांघ सकती है।

हनुमान जी का भय, उनकी झिझक, उनका छोटा महसूस करना—

सब उसी पल मिट गया, जब किसी ने उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाई।

और उसी पल उनमें एक साधारण वानर नहीं, "महावीर हनुमान" जन्मे।

अब इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखिए। आपके भीतर भी वही शक्ति है, जिसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं।

आपकी समस्या क्षमता की नहीं, आत्मविश्वास की है।

हीनभावना आपके भीतर की आग को बुझाती नहीं, बस धुएँ में छुपा देती है।

सच यह है कि आपके भीतर एक हनुमानजी बैठे है जो जागने का इंतज़ार कर रहे हैं ।

श्रीराम ने कभी किसी की तुलना नहीं की। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम कम हो या तुम ज्यादा हो।

उन्होंने हर किसी की शक्ति पहचानी। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनाई और हर व्यक्ति को उसकी क्षमता तक पहुँचाया।

रामजी का संदेश साफ था—स्वयं को छोटा मत समझो।

तुम्हारे भीतर वो है जो संसार बदल सकता है।

इसीलिए यह सवाल खुद से ज़रूर पूछिए कि कहीं आप वह हनुमान तो नहीं जो अपने ही सामर्थ्य से अनजान है ?

कहीं आप वह इंसान तो नहीं, जो दुनिया से नहीं—खुद से हार रहा है ?

अगर हाँ, तो आज से याद रखिए— हीनभावना आपका सत्य नहीं है।

आपकी क्षमता आपका सत्य है।

https://tolwa.com/about.html
tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com
09811732095

आज का साइबर सुरक्षा विचार

पिंकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य उज्जवला योजना दिल्ली प्रदेश

*ऑपरेशन Cy-Hawk दिल्ली पुलिस द्वारा शुरु किया गया एक रणनीतिक साइबर अपराध विरोधी अभियान है, जिसका उद्देश्य संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करना, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाना और भारत के साइबर हाइजीन मॉडल को सक्रिय प्रवर्तन और नागरिक जागरूकता के माध्यम से मजबूत करना है

ऑपरेशन Cy-Hawk क्या है ? ऑपरेशन Cy-Hawk, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जो बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई है। यह धोखाधड़ी सिंडिकेट्स, डिजिटल पहचान की चोरी, वित्तीय घोटालों और तकनीक आधारित शोषण को लक्षित करता है, जिसमें खुफिया जानकारी, तकनीक और जनसंपर्क का मिश्रण शामिल है।

ऑपरेशन Cy-Hawk के तहत किए गए प्रमुख प्रयास दिल्ली पुलिस ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Cy-Hawk को इस तरह लागू किया:

1. संगठित साइबर अपराध पर कार्रवाई
1. अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क के सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी, जिनमें UltraViewer और AnyDesk जैसे रिमोट एक्सेस टूल्स का उपयोग करने वाले शामिल है ।

२. फर्जी कॉल सेंटर, फ़िशिंग हब और म्यूल अकाउंट ऑपरेटरों पर कार्यवाही ।
२. रियल-टाइम इंटेलिजेंस और निगरानी
1. AI आधारित विश्लेषण, IP ट्रेसिंग और डिजिटल फॉरेंसिक का उपयोग कर धोखाधड़ी के पैटर्न को ट्रैक किया गया है ।।
२. CERT-In, बैंकों और टेलीकॉम प्रदाताओं के साथ मिलकर धोखाधड़ी प्रयासों को रोकना और संदिग्ध लेनदेन को फ्रीज़ करना ।
३. जन जागरूकता और आउटरीच
1. सोशल मीडिया, व्हाट्सएप्प और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से साइबर सुरक्षा सलाह ।
२. नागरिकों के लिए रिमोट एक्सेस स्कैम, OTP धोखाधड़ी और सेक्सटॉर्शन से बचने के लिए सलाह
4. क्षमता निर्माण और अधिकारी प्रशिक्षण
1. पुलिस कर्मियों के लिए साइबर अपराध जांच, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और पीड़ित सहायता पर तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
२. साइबर मामलों में तेज़ FIR पंजीकरण और प्रतिक्रिया के e FIR System

डिजिटल सुरक्षित भारत मॉडल पर प्रभाव ऑपरेशन Cy-Hawk निम्नलिखित तरीकों से डिजिटल सुरक्षित भारत की व्यापक दृष्टि में योगदान देता है:

1. नागरिक विश्वास को बढ़ाता है: तेज़ कार्रवाई और पारदर्शिता दिखाकर यह नागरिकों को आश्वस्त करता है कि डिजिटल धोखाधड़ी को गंभीरता से लिया जा रहा है।
२. रोकथाम ढांचे को मजबूत करता है: SOPs और सार्वजनिक सलाह से पीड़ितों की संख्या कम होती है और साइबर हाइजीन बेहतर होती है।
३. संस्थागत तत्परता को बढ़ाता है: प्रशिक्षित अधिकारी और तकनीक-सक्षम पुलिसिंग प्रणाली को बदलते खतरों के प्रति अधिक लचीला बनाते हैं।
4. सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देता है: बैंकों, टेक कंपनियों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी से बहु-हितधारक सुरक्षा नेटवर्क बनता है।

सतर्क रहें। सशक्त बनें, डिजिटल सतर्कता = राष्ट्रीय सुरक्षा

डिजिटल अरेस्ट का नया जाल: वीडियो कॉल पर 'हिरासत' में लेकर खाली कर रहे खाते

पिंकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश

भारत में साइबर अपराध का नया रूप 'डिजिटल अरेस्ट' तेजी से फैल रहा है। पुलिस, सीबीआई, साइबर सेल या सरकारी विभाग के नाम पर वीडियो कॉल के जरिये लोगों को घंटों तक "हिरासत" में रखकर लाखों रुपये ऐंठने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ और कानूनविद साफ कहते हैं कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं, फिर भी हजारों लोग इस जाल में फँस चुके हैं क्योंकि ठग सरकारी अधिकारियों की आवाज़, वर्दी और कागजात तक की नकल कर लेते हैं।

कैसे काम करता है डिजिटल अरेस्ट का गिरोह ? जांच एजेंसियों के अनुसार, ठग पहले किसी अनजान नंबर से कॉल करते हैं और खुद को—
पुलिस अधिकारी,
CBI/ED/NCB का अधिकारी,
साइबर सेल अधिकारी,
या कूरियर कंपनी/बैंक का प्रतिनिधि
बताते हैं। इसके बाद वे एक फर्जी मामला बनाते हैं जैसे—
आपके आधार पर कोई सिम कार्ड अपराध में इस्तेमाल हुआ
आपके नाम से पार्सल पकड़ा गया जिसमें ड्रग्स/कार्ड/नकदी मिली
आपका बैंक खाता मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है
डर का माहौल बनाकर वे कहते हैं कि आपको फिलहाल 'डिजिटल अरेस्ट' में लिया जा रहा है, इसलिए:
वीडियो कॉल बंद नहीं करना,
किसी से बात नहीं करना,
तुरंत अपने बैंक खाते "सुरक्षित" करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करना है।

पीड़ित मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर उनके बताए खाते में पैसे भेज देता है, और ठग लाखों रुपये लेकर गायब हो जाते हैं।

कानून क्या कहता है ? कानून विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। किसी नागरिक को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को भौतिक रूप से नोटिस देना या वारंट पेश करना अनिवार्य है। कानून के तहत न तो वीडियो कॉल पर पूछताछ संभव है, न ही किसी को मोबाइल कैमरा ऑन रखकर "कस्टडी" में रखा जा सकता है। इसलिए किसी भी अधिकारी का ऐसा दावा स्वत: ही संदिग्ध माना जाना चाहिए।

क्यों बढ़ रहा है यह साइबर अपराध ? लोगों में कानूनी जानकारी की कमी
सरकारी संस्थाओं का भय
वीडियो कॉल पर नकली पहचान बनाना आसान
त्वरित मोबाइल बैंकिंग से ठगों को फायदा
विदेशी और स्थानीय गिरोहों का गठजोड़
साइबर सेल के अनुसार, यह अपराध विशेष रूप से नौकरीपेशा, छात्र तथा महिलाओं को निशाना बनाता है क्योंकि वे अचानक कॉल आने पर डर के माहौल में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं।

पीड़ितों के दर्दभरे अनुभव
कई मामलों में कॉलर्स पीड़ित को 8–10 घंटे तक वीडियो कॉल पर रोके रखते हैं।
कुछ मामलों में लोग ऑफिस, घर और यहां तक कि शौचालय तक कैमरा ऑन करके जाते हैं।
ठग कहते हैं कि "आप अभी पुलिस कस्टडी में हैं, कैमरा बंद किया तो गिरफ्तारी हो जाएगी।"
यह मनोवैज्ञानिक दबाव अक्सर लोगों को आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर तोड़ देता है।

कैसे बचें डिजिटल अरेस्ट के जाल से ?
किसी भी अजनबी कॉल पर पर्सनल डेटा, OTP, बैंक विवरण न दें
पुलिस/CBI कभी फोन पर पैसे जमा कराने को नहीं कहती
किसी भी वीडियो कॉल पर "कस्टडी" का दावा 100% फर्जी होता है
कॉल आते ही तुरंत काटें और नंबर ब्लॉक करें
1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत करें
cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें
डिजिटल अरेस्ट केवल एक ठगी का मनोवैज्ञानिक हथियार है। अपराधी डर, भ्रम और सरकारी नाम का सहारा लेकर नागरिकों को मानसिक रूप से जकड़ते हैं।
समय आ गया है कि लोग समझें—
डिजिटल अरेस्ट कानून में नहीं, सिर्फ अपराधियों की चाल में है।

आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी

* सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी
* युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी
* महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी
* 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
* फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी
* 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ़्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी
* ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी
* जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्युरिटी की गारंटी
* इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी

यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है।

#श्रमेव_जयते
#ShramevJayateh

पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य उज्जवला योजना दिल्ली प्रदेश

डॉक्टर से मिलने से पहले कृपया इसे एक बार पढ़ लें

आज डाक्टरी पेशा!!! सेवा नहीं शुद्ध व्यवसाय है... आपको दो या तीन दिन बुखार रहा। अगर आपने कोई दवा भी नहीं ली होती, तो कुछ दिनों में आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाता।

लेकिन आप डॉक्टर के पास चले गए।

शुरुआत में ही डॉक्टर ने कई टेस्ट लिख दिए। टेस्ट के नतीजों में बुखार की कोई खास वजह नहीं मिली। हालांकि, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा... जो कि आमतौर पर सामान्य है। बुखार तो उतर गया, लेकिन अब आप सिर्फ बुखार के मरीज नहीं रहे...

डॉक्टर साहब ने आपको बताया: "आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। शुगर भी थोड़ी बढ़ी हुई है। इसका मतलब है कि आप प्री-डायबिटिक हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल और शुगर नियंत्रित करने की दवाएं लेनी होंगी।"

इसके साथ ही खाने-पीने की कई पाबंदियां लग गईं...

हो सकता है आपने खाने की पाबंदियों को सख्ती से न माना हो — लेकिन दवाएं खाना आपने नहीं भूला... तीन महीने बीत गए। फिर टेस्ट हुए।

आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया।

एक और दवा लिख दी गई।

अब आप तीन दवाएं खा रहे थे। यह सब सुनकर आपकी चिंता बढ़ गई। ₹अब क्या होगा?₹

इस चिंता की वजह से आपकी नींद उड़ गई।

डॉक्टर ने नींद की गोली लिख दी — और अब आपकी दवाएं चार हो गईं।

इन सभी दवाओं को खाने के बाद आपको एसिडिटी और सीने में जलन होने लगी।

डॉक्टर ने सलाह दी: ₹खाने से पहले खाली पेट गैस की गोली खा लिया करें।₹

अब आप पांच दवाएं खा रहे थे।

छह महीने बीत गए। एक दिन आपको सीने में दर्द हुआ और आप इमरजेंसी में पहुंच गए।

पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा: "अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। वरना गंभीर हो सकता था।"

और टेस्ट सुझाए गए।

कई महंगे टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने बताया: "अपनी मौजूदा दवाएं जारी रखें। लेकिन अब दिल के लिए दो और दवाएं शामिल कर लें। साथ ही, आपको

एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए।"

अब आप सात दवाएं खा रहे थे।

कार्डियोलॉजिस्ट के सुझाव पर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गए।

उन्होंने एक और शुगर की दवा और थायरॉइड की गोली शामिल कर दी, क्योंकि थायरॉइड का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ था। अब आपकी कुल दवाएं नौ हो गईं। धीरे-धीरे आप यह मानने लगे कि आप वाकई बीमार हैं: दिल का मरीज

डायबिटीज

अनिद्रा

गैस की समस्या

थायरॉइड की समस्या

किडनी की समस्या

... और यह सूची बढ़ती रही।

किसी ने आपको नहीं बताया कि आप इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और जीवनशैली में बदलाव लाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

बल्कि आपको बार-बार बताया गया कि आप एक गंभीर मरीज हैं, कमजोर हैं, अक्षम हैं और टूटे हुए इंसान हैं। छह महीने बाद, इन सभी दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से आपको पेशाब की समस्या होने लगी।

और टेस्ट से किडनी की समस्या का पता चला। डॉक्टर ने और टेस्ट किए। रिपोर्ट देखकर कहा: ₹क्रिएटिनिन का स्तर थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन चिंता न करें — जब तक आप नियमित रूप से दवाएं लेते रहेंगे।"

उन्होंने दो और दवाएं शामिल कर दीं।

अब आप ग्यारह दवाएं खा रहे थे। अब आप खाने से ज्यादा दवाएं खा रहे थे, और इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से आप धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहे थे। अगर शुरुआत में, जब आप पहली बार बुखार की वजह से डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने सिर्फ इतना कह दिया होता: ₹चिंता करने की जरूरत नहीं। यह सिर्फ हल्का बुखार है। दवा की जरूरत नहीं। आराम करें, खूब पानी पिएं, ताजे फल और सब्जियां खाएं, सुबह की सैर करें — बस। किसी दवा की जरूरत नहीं।"

लेकिन फिर... डॉक्टर और दवा कंपनियां अपनी रोजी कैसे कमातीं? ### सबसे बड़ा सवाल: डॉक्टर किस आधार पर मरीजों को हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी या किडनी की बीमारी का मरीज घोषित करते हैं? यह मानक कौन तय करता है? आइए इस पर थोड़ा गहराई से जाएं: 1979 में, शुगर का स्तर 250 mg/dl को डायबिटीज माना जाता था। उस समय दुनिया की सिर्फ 3.5% आबादी टाइप 2 डायबिटीज में गिनी जाती थी।

1997 में, इंसुलिन बनाने वाली कंपनियों के दबाव में, डायबिटीज की सीमा को 200 mg/dl तक कम कर दिया गया, जिससे अचानक डायबिटीज के मरीजों की संख्या 3.5% से 8% हो गई — यानी 4.5% ज्यादा लोगों को बिना किसी वास्तविक लक्षण के डायबिटीज का लेबल लगा दिया गया।

1999 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस गाइडलाइन को स्वीकार कर लिया।

इंसुलिन कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया और और फैक्ट्रियां खोल लीं। 2003 में, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (ADA) ने फास्टिंग शुगर के स्तर को 100 mg/dl तक कम करके प्री-डायबिटिक का मानक बना दिया।

नतीजतन, 27% लोग बेवजह डायबिटीज की श्रेणी में आ गए।

वर्तमान में, ADA के अनुसार, खाने के बाद शुगर 140 mg/dl को डायबिटीज माना जाता है।

इसकी वजह से, दुनिया की लगभग 50% आबादी को अब डायबिटीज का लेबल लग चुका है... जिनमें से कई वास्तव में बीमार नहीं हैं।

भारतीय दवा कंपनियां इसे और कम करके HbA1c 5.5% करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि और लोगों को मरीज बनाकर दवाओं की बिक्री बढ़ाई जा सके। कई विशेषज्ञों का मानना है कि HbA1c को 11% तक डायबिटीज नहीं मानना चाहिए। ### एक और उदाहरण: 2012 में, एक बड़ी दवा कंपनी पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। उन पर आरोप था कि 2007-2012 के बीच उनकी डायबिटीज की दवा ने दिल के दौरे का खतरा 43% तक बढ़ा दिया था।

कंपनी को यह पहले से पता था लेकिन मुनाफे के लिए जानबूझकर छिपाया गया।

इस दौरान उन्होंने 300 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया। यही है आज का ₹आधुनिक चिकित्सा तंत्र₹! सोचें... विचार करना शुरू करें...

महंगे शैम्पू को कहें बाय और घर में रखी इन चीजों से धोएं बाल; स्कैल्प होगा साफ, बालों में आएगी चमक

महंगे शैम्पू और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की बजाय प्राकृतिक चीजों (Natural Hair Cleansers) का इस्तेमाल करने से बालों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। ये घरेलू नुस्खे न केवल सस्ते हैं बल्कि बालों को प्राकृतिक रूप से मजबूत और चमकदार भी बनाते हैं। आइए जानते हैं बाल धोने के लिए किन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आजकल बाजार में कई तरह के शैम्पू मौजूद हैं, जो बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाने का दावा करते हैं। लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं

अगर आप भी महंगे शैम्पू से परेशान हो चुके हैं और नेचुरल तरीके (Natural Cleansers for Hair) से अपने बालों की देखभाल करना चाहते हैं, तो घर में मौजूद कुछ चीजें (Homemade Shampoo Alternatives) आपके काम आ सकती हैं। ये न केवल स्कैल्प को साफ करेंगी, बल्कि बालों में नेचुरल चमक भी लौटाएंगी। आइए जानें बालों को साफ करने के लिए नेचुरल क्लींजर।

1. रीठा और शिकाकाई- नेचुरल क्लींजर रीठा और शिकाकाई सदियों से बालों को धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ये दोनों ही नेचुरल क्लींजर की तरह काम करते हैं और बालों से गंदगी हटाने के साथ-साथ उन्हें मजबूत भी बनाते हैं।

कैसे इस्तेमाल करें?

1. रातभर रीठा और शिकाकाई को पानी में भिगोकर रख दें।

2. सुबह इस पानी को उबालकर ठंडा कर लें और बालों में लगाएं।

3. हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज

करें और 10-15 मिनट बाद बालों को साफ पानी से धो लें।

2. दही और नींबू- डैंड्रफ और ऑयल कंट्रोल के लिए दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्कैल्प को साफ करता है और डैंड्रफ को दूर करता है। नींबू का रस बालों की ग्रिसीनेस को कम करता है और स्कैल्प को फ्रेश रखता है।

कैसे इस्तेमाल करें?

1. 2 चम्मच दही में आधा नींबू निचोड़ें।

2. इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर लगाएं।

3. 20 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें।

3. एलोवेरा- स्कैल्प हाइड्रेशन और हेयर ग्रोथ के लिए एलोवेरा जेल में एंजाइम्स और विटामिन्स होते हैं, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। यह स्कैल्प को मॉइश्चराइज करता है और खुजली से राहत दिलाता है।

कैसे इस्तेमाल करें?

1. ताजा एलोवेरा जेल निकालकर स्कैल्प पर लगाएं।

2. 30 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

4. आंवला और नारियल तेल- बालों को मजबूत बनाने के लिए आंवला विटामिन-सी से भरपूर होता है, जो बालों को काला और घना बनाता है। नारियल तेल बालों की डीप कंडीशनिंग भी करता है।

कैसे इस्तेमाल करें?

1. आंवला पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर गर्म करें।

2. इस तेल से बालों की मसाज करें और 1 घंटे बाद धो लें।

5. मेथी के बीज- हेयर फॉल और डैमेज रिपेयर के लिए मेथी के बीज प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भरपूर होते हैं, जो बालों का झड़ना कम करते हैं।

कैसे इस्तेमाल करें?

1. मेथी दानों को रातभर भिगोकर पेस्ट बना लें।

2. इसे बालों में लगाकर 30 मिनट बाद धो लें।

तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं बाल? तो नारियल तेल में मिलाकर लगाएं कैस्टर ऑयल, हेयर फॉल भी हो जाएगा कम

बालों को लंबा और मजबूत बनाने के लिए नारियल तेल में अरंडी का तेल (Oils for Hair Growth) मिलाकर लगाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कैस्टर ऑयल बालों के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल में से एक है। इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से बालों से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए जानें नारियल तेल में अरंडी का तेल मिलाकर लगाने के फायदे।

खूबसूरत और लंबे बालों (Long and Healthy Hair) की चाह किसे नहीं होती। सिल्की, शाइनी और घने बालों से खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं। लेकिन प्रदूषण, धूल-मिट्टी, खान-पान और हार्मोनल बदलाव जैसी कई वजहों से बाल कमजोर, रूखे और बेजान हो जाते हैं। इससे न सिर्फ लुक खराब होता है, बल्कि तनाव भी बढ़ता है। ऐसे में बालों की खूबसूरती लौटाने के लिए हम केमिकल वाले कई हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनसे फायदे की जगह नुकसान भी पहुंच सकता है।

इसलिए बालों को हेल्दी और खूबसूरत बनाने के लिए नेचुरल उपायों को अपनाना ज्यादा फायदेमंद है। इन्हीं उपायों में एक उपाय नारियल तेल में अरंडी का तेल (Castor Oil and Coconut Oil for Hair) मिलाकर लगाना भी है। ये दोनों ही तेल बालों के लिए काफी लाभदायक होते हैं और कई तरह की परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। आइए जानें बालों में नारियल और अरंडी का तेल लगाने के फायदे (Benefits of Castor and

Coconut Oil) और इन्हें लगाने का सही तरीका क्या है।

नारियल तेल और अरंडी का तेल लगाने के फायदे

1. बाल झड़ना कम होता है- धूल-मिट्टी और प्रदूषण की वजह से बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा, पोषण की कमी के कारण भी बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। लेकिन नारियल तेल में अरंडी का तेल मिलाकर लगाने से बालों का झड़ना कम हो सकता है। ये बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। इससे बालों का टूटना-झड़ना कम होता है।

2. नए बाल उगाने में मदद- थोड़े बहुत बाल टूटना आम बात है, लेकिन जब इन टूटे हुए बालों की जगह नए बाल उगना बंद हो जाएं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। नारियल तेल में अरंडी का तेल मिलाकर लगाने से नए बाल उगाने में काफी मदद मिल सकती है।

3. बाल लंबे होते हैं- अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपके बाल तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, तो नारियल और अरंडी का तेल लगाकर देखें। अरंडी का तेल बालों को लंबा करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इससे जड़ों को पोषण मिलता है और बाल लंबे होते हैं।

4. स्कैल्प की खुजली से छुटकारा- नारियल तेल में अरंडी का तेल मिलाकर लगाने से स्कैल्प की खुजली से छुटकारा मिलता है। डैंड्रफ या गंदगी की वजह से आमतौर पर स्कैल्प में खुजली होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर लंबे समय से स्कैल्प में खुजली हो रही है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें।

कैसे लगाएं नारियल और अरंडी का तेल? अरंडी का तेल काफी हैवी होता है। इसलिए इसे किसी कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर लगाना चाहिए। नारियल तेल एक परफेक्ट कैरियल ऑयल का काम करता है। इन दोनों तेलों के मिलाकर, इससे स्कैल्प की मालिश करें और 30 मिनट के लिए तेल को स्कैल्प में अब्जॉर्ब होने दें। इसके बाद बालों को शैम्पू से धो लें।

बालों के झड़ने और रूसी से हैं परेशान, तो यहां बताए 3 तरीकों से करें कपूर का इस्तेमाल

आजकल बालों का झड़ना और रूसी एक आम समस्या बन गई है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं। कई घरेलू नुस्खे इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं जिनमें से कपूर भी एक है। इसमें एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प को हेल्दी रखने और बालों की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जान लीजिए इसके इस्तेमाल के 3 सिंपल तरीके।

कंघी करते वक्त बालों का गुच्छा देखकर दिल बैठ जाता है और कंधों पर गिरी हुई रूसी किसी भी मौके पर शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। जी हां, अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

आपकी रसोई में मौजूद एक छोटी-सी चीज- कपूर, इन मुश्किलों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। बता दें, यह कोई आम सामग्री नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकृति का एक ऐसा खजाना है जो आपके बालों को फिर से हेल्दी और घना बना सकता है। आइए जानते हैं कपूर के उन 3 घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनसे आप बालों के झड़ने और रूसी को हमेशा के लिए बाय-बाय कह सकते हैं।

1. कपूर और नारियल तेल का प्रयोग

नारियल तेल बालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशनर है और यह बालों को पोषण देता है। जब इसे कपूर के साथ मिलाया जाता है, तो यह रूसी और स्कैल्प के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो बालों के झड़ने का एक कारण हो सकता है।

सामग्री:

1. 2 बड़े चम्मच नारियल तेल

2. 1/2 चम्मच कपूर का पाउडर (बारीक पिसा हुआ)

विधि:

1. एक कटोरी में नारियल तेल लें और उसमें कपूर का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।

2. इस मिश्रण को हल्का गरम करें।

3. गरम तेल को अपने स्कैल्प पर धीरे-धीरे मसाज करें।

4. रात भर या कम से कम 2 घंटे के लिए इसे लगा रहने दें।

5. अगले दिन हल्के शैम्पू से बालों को धो लें।

6. इसे हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें।

2. कपूर और दही का हेयर मास्क दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्कैल्प को साफ करने और रूसी को कम करने में मदद करता है। कपूर के एंटी-फंगल गुण मिलकर स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं।

सामग्री:

1. 4 बड़े चम्मच दही

2. 1/2 चम्मच कपूर का पाउडर

विधि:

1. एक कटोरी में दही लें और उसमें कपूर का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

2. इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह से लगाएं।

3. 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें।

4. हल्के शैम्पू से बालों को धो लें।

5. इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें।

3. कपूर का तेल आप सीधे कपूर का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी कैरियर ऑयल, यानी जैतून या बादाम जैसे तेल के साथ मिलाकर लगाना बेहतर होता है ताकि यह स्कैल्प पर नुकसानदायक न साबित हो।

सामग्री:

1. 1 बड़ा चम्मच कैरियर ऑयल (जैतून का तेल, बादाम का तेल, या नारियल तेल)

2. कुछ बूंदें कपूर का तेल (एसेंशियल ऑयल)

विधि:

1. कैरियर ऑयल में कपूर के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं।

2. इस मिश्रण से अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें।

3. कम से कम 1 घंटे के लिए इसे लगा रहने दें।

4. फिर शैम्पू से बालों को धो लें।

5. इसे हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

नेचुरली देना है बालों को गहरा काला रंग, तो मेहंदी में इन 3 चीजों को मिलाकर करें अप्लाई

बालों को कलर करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल कई लोग करते हैं लेकिन अगर आपको भी इसके बाद नारंगी होने वाले बालों से शिकायत रहती है तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम बताएंगे कि कैसे कुछ खास चीजों को मेहंदी में मिक्स करके अप्लाई करने से बालों को नेचुरली काला किया जा सकता है। आइए जानें।

सफेद होते बालों को छिपाना आजकल एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में, ज्यादातर लोग केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, जो बालों को तो तुरंत काला तो कर देते हैं, लेकिन लंबे समय में उन्हें रूखा और बेजान बनाकर छोड़ते हैं।

अगर आप भी अपने बालों को नेचुरली से घना बनाकर गहरा काला रंग देना चाहते हैं, तो मेहंदी से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। जी हां, बस जरूरत है मेहंदी में कुछ खास चीजें मिलाकर लगाने की। आइए आज हम आपको बताएंगे ऐसी 3 चीजें, जिन्हें मेहंदी में मिलाने से आपके बालों को मिलेगा गहरा काला रंग और साथ ही पोषण भी

मेहंदी में मिक्स करें 3 चीजें

1. कॉफी पाउडर कॉफी सिर्फ आपकी सुबह की थकान ही नहीं मिटाती, बल्कि यह बालों को गहरा और काला रंग देने में भी मदद करती है। कॉफी में मौजूद टेनिन मेहंदी के रंग को और भी गाढ़ा कर देते हैं।

ऐसे करें इस्तेमाल

1. एक कप पानी में 2-3 चम्मच कॉफी पाउडर डालकर अच्छी तरह उबाल लें।

2. जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे अपनी भिगोई हुई मेहंदी में मिलाएं।

3. ध्यान रखें कि मिश्रण में कोई गांठ न रहे।

4. इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए लगा रहने दें या बेहतर रिजल्ट्स के लिए रात भर लगाएं।

2. लोहे का बर्तन यह पढ़कर शायद आपको भी हैरानी हो, लेकिन लोहे के बर्तन का इस्तेमाल मेहंदी के रंग को गहरा करने में बहुत मदद करता है। लोहे के कण मेहंदी के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होते हैं, जिससे बालों को मिलने वाला रंग और भी गहरा काला हो जाता है।

ऐसे करें इस्तेमाल

1. मेहंदी को चाय या कॉफी के पानी के साथ मिलाकर किसी लोहे की कड़ाही या पैन में भिगोएं।

2. इसे कम से कम 6-8 घंटे या रात भर लोहे के बर्तन में ही रहने दें।

3. सुबह तक आप देखेंगे कि मेहंदी का रंग और भी गहरा हो गया है।

3. आंवला पाउडर आंवला बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो बालों को मजबूत बनाने, झड़ने से रोकने और उन्हें नेचुरली काला करने में भी मदद करता है।

ऐसे करें इस्तेमाल करें

1. 2-3 चम्मच आंवला पाउडर को मेहंदी के घोल में मिलाएं।

2. इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई गांठ न रहे।

3. आंवला पाउडर मेहंदी के रंग को थोड़ा भूरा कर सकता है, लेकिन यह आपके बालों को गहरा काला शेड देने में मदद करेगा।

डिजिटल हल, मानवीय सम्मानः न्यायपालिका का नया चेहरा

जब न्यायपालिका की गरिमा तकनीक के साथ सहजता से मिलती है, तभी समाज की असली प्रगति दिखाई देती है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का हालिया फैसला केवल एक कागजी आदेश को रद्द करने तक सीमित नहीं है; यह उन सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के प्रति गहन सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने दशकों तक न्याय के तराजू को निर्भीक और निष्पक्ष बनाए रखा। वे लोग, जिन्होंने अपना जीवन न केवल कानून बल्कि समाज की विश्वासनीयता और नैतिक संतुलन के लिए समर्पित किया, अब हर नवंबर की जटिल औपचारिकताओं से मुक्त रहेंगे। यह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मानवता, गरिमा और न्याय की असली भावना को पुनः प्रतिष्ठित करने वाला ऐतिहासिक कदम है।

13 दिसंबर 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र ने राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत मेडिकल भत्ता और घरेलू भत्ता जारी रखने के लिए उन्हें हर वर्ष अपने ही जिले में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था। यह नियम शायद सामान्य पेंशनभोगियों के लिए सहज और उपयुक्त प्रतीत हो सकता था, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवनभर निष्पक्ष और निर्भीक न्याय के लिए समर्पण किया, यह प्रथा उनके सम्मान और गरिमा के अनुरूप नहीं थी। फार्मर जजेस वेलफेयर एसोसिएशन ने इस असंवैधानिक और अपमानजनक प्रथा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, स्पष्ट करते हुए कि राज्य सरकार का अधिकार कभी भी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की गरिमा को आहत करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने अपने संक्षिप्त किन्तु निर्णायक फैसले में स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कोई सामान्य पेंशनर नहीं हैं। उन्होंने संविधान की शपथ के तहत न्याय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का पालन किया, और उनका जीवन न्याय की सेवा में समर्पित रहा। ऐसे व्यक्तियों को बार-बार अपनी जीवित उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए बाध्य करना न्यायपालिका की आत्मा और गरिमा पर चोट है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन की पुष्टि डिजिटल माध्यमों या बैंक रिकॉर्ड के माध्यम से सहजता से की जा सकती है, जिससे किसी पूर्व न्यायाधीश को अदालत में तलब करना न केवल अनावश्यक, बल्कि सम्मान के विपरीत है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने परिपत्र को वापस ले लिया और रिटायर्ड जजों को स्थायी राहत प्रदान की।

यह निर्णय केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे देश में मिसाल बनेगा और अन्य राज्यों में भी रिटायर्ड न्यायाधीशों और उच्च अधिकारियों के लिए सम्मान और गरिमा की नई दिशा स्थापित करेगा। यह साबित करता है कि तकनीक और प्रशासनिक प्रक्रिया का वास्तविक

उद्देश्य इंसान की सुविधा और सम्मान होना चाहिए, न कि उनकी अपमानजनक जांच। डिजिटल इंडिया के युग में, जब आधार, पैन, बैंक खाता और मोबाइल जैसी सुविधाएँ आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी पुराने कागजी दस्तावेजों के लिए बुजुर्गों को समय और श्रम गंवाने के लिए बाध्य करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि संवेदनशीलता और सम्मान की कमी का भी प्रतीक है।

डिजिटल समाधान के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करना अब न केवल संभव, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी है। आज के डिजिटल युग में यह सहज है कि सभी जीवन प्रमाणित प्रक्रियाएँ बिना किसी कठिनाई और झंझट के ऑनलाइन पूरी की जा सकें। बायोमेट्रिक आधार अपडेट, बैंक खाता सक्रियता का सत्यापन, मोबाइल संदेश के माध्यम से जीवन पुष्टि या निष्क्रियता पर अलर्ट जैसे उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं। इससे न केवल रिटायर्ड न्यायाधीशों, बल्कि सभी पेंशनभोगियों को सहज, सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से अपनी जीवन पुष्टि कराने की सुविधा मिलती है। तकनीक का यह प्रयोग केवल सुविधाजनक नहीं है; यह समाज में सम्मान, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण को भी मजबूती से स्थापित करता है। मध्यप्रदेश का यह निर्णायक कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब डिजिटल समाधान मानव सेवा और गरिमा के लिए काम करता है, तब न्याय और समाज दोनों की भलाई सुनिश्चित होती है।

सच्ची प्रभावशीलता इस तथ्य में निहित है कि यह राहत किसी विशेष लाभ की मांग नहीं थी—यह केवल सम्मान की मांग थी। जब न्यायपालिका ने स्वयं अपने पूर्व सदस्यों का सम्मान सुनिश्चित किया, तो इसने यह साबित कर दिया कि संस्था न केवल जीवित है, बल्कि संवेदनशील और न्यायप्रिय भी है। छोटे प्रशासनिक निर्णय भी बड़े संदेश दे सकते हैं, और यह फैसला यह संदेश देता है कि समाज और राज्य के लिए न्याय के कार्यकर्ताओं का ऋण चुकाना एक अनिवार्य कर्तव्य है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यह ऋण पूरी गरिमा के साथ चुका दिया। अब समय आ गया है कि पूरे देश में रिटायर्ड न्यायाधीशों और सभी न्याय कर्मियों की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जाए। न्यायाधीश भले ही रिटायर हो जाएँ, लेकिन न्याय और उसके सम्मान का गौरव कभी रिटायर नहीं होता।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

यह कैसा कर्तव्य...!

भाई यह कैसी रहीं 'माता-पिता' की माया,
घर में हुए दो मुख्यमंत्री बेटा पढ़ न पाया।
क्यों? नहीं समझ पाए ये शिक्षा का महत्व,
क्या? 'क्रिकेट' में समाया था सम्पूर्ण सत्व।

इन 'पालकों' ने यह कैसा निभाया कर्तव्य,
स्वघोषित मुख्यमंत्री होना यहीं भवितव्य।
स्वयं अपने ही पास जब रखीं है लालटेन,
क्यों? ना दी पढ़ने के लिए उसे कॉपी-पेन।

पता नहीं कहां-कहां फैला था जंगल राज,
घुलना थे इनके कानों में नम्रतारूपी साज़।
तब बन पाते यहीं 'जनमानस' की आवाज,
दिलों पर करते राज मिलती सत्ता परवाज़।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

सभी हिन्दूओ, आपके जानने और समझ कर फैसला लेने योग्य तथ्य

1. ऑटो वाले ने मुंह मांगी कीमत मांगी और ब्लैक मेल कर बाध्य किया ओला-उबर के लिए!

2. BSNL कस्टमर केयर वालों ने 2 -2 घण्टे होल्ड पर रखकर मजबूर किया एयरटेल, वोडाफोन के लिए!

3. कुछ दुकानदारों ने दो गुना तीन गुना कीमत वसूली और नकली माल देकर मजबूर किया ऑनलाइन शॉपिंग के लिए!

4. सरकारी अस्पताल के लापरवाही और ग़ैरजिम्मेदाराना व्यवहार ने मजबूर किया प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए,

5. रोडवेज के धीमे, असुविधाजनक सफर ने मजबूर किया प्राइवेट बसों में डीलक्स कोच के लिए!

6. सरकारी स्कूल में रिक्त पद, लचर पढ़ाई, अव्यवस्थित प्रबंध और दायित्वबोध की कमी ने मजबूर किया प्राइवेट स्कूल के लिए!

7. सरकारी बैंक की दादागिरी, ने मजबूर किया प्राइवेट बैंक में खाता खोलने को!

प्रशन -कितने लोगों को भारत संचार निगम लिमिटेड की चिंता है?

उत्तर- सभी को,

प्रशन कितने लोग भारत संचार निगम लिमिटेड की सिम का प्रयोग करते हैं?

उत्तर- कोई नहीं।

प्रशन - सरकारी स्कूल की चिंता कितने लोग करते हैं?

उत्तर- सभी करते हैं!

प्रशन - सरकारी स्कूल में कितने लोगो के बच्चे पढ़ते हैं?

उत्तर- किसी के नहीं।

प्रशन - कितने लोग पालीथीन मुक्त वातावरण चाहते हैं?

उत्तर - सभी चाहते हैं!

प्रशन - पालीथीन का प्रयोग कौन नहीं करता?

उत्तर- सभी करते हैं।

प्रशन -भ्रष्टाचार मुक्त भारत कौन कौन चाहते हैं?

उत्तर-सभी चाहते!

प्रशन - अपने व्यक्तिगत काम के लिए कितने लोगों ने रिश्वत नहीं दी?

उत्तर - सभी ने अपने व्यक्तिगत काम के लिए किसी न किसी को किसी न किसी रूप में रिश्वत जरूर दी है।

प्रश्न- गिरते रुपये की चिंता कितने लोग करते हैं?

उत्तर- सभी करते हैं।

प्रश्न- कितने लोग सिर्फ

स्वदेशी सामान खरीदते हैं?

उत्तर- कोई नहीं।

प्रश्न- यातायात की बिगड़ी हालात से कौन कौन दुखी है?

उत्तर - सभी दुखी।

प्रश्न- यातायात के नियमों को 100% पालन कौन कौन करता है?

उत्तर- कोई नहीं।*

प्रश्न- बदलाव कौन कौन चाहते हैं?

उत्तर- सभी चाहते।

प्रश्न- खुद कितने लोग बदलना चाहते हैं?

उत्तर - कोई नहीं।

संभलने की जरूरत है !!

1. चोटियां छोड़ी,
2. टोपी, पगड़ी छोड़ी,
3. तिलक, चंदन छोड़ा
4. कुर्ता छोड़ा, धोती छोड़ी,
5. यज्ञोपवीत छोड़ा,
6. संध्या वंदन छोड़ा।
7. रामायण पाठ, गीता पाठ छोड़ा,
8. महिलाओं, लड़कियों ने साड़ी छोड़ी, बिछिया छोड़े, चूड़ी छोड़ी, दुपट्टा, चुनरी छोड़ी, मांग बिन्दी छोड़ी।
9. पैसे के लिये, बच्चे छोड़े (आया पालती है)
10. संस्कृत छोड़ी, हिन्दी छोड़ी,
11. श्लोक छोड़े, लोरी छोड़ी।
12. बच्चों के सारे संस्कार (बचपन के) छोड़े,
13. सुबह शाम मिलने पर राम राम छोड़ी,
14. पांव लागूं, चरण स्पर्श, पैर छूना छोड़े,
15. घर परिवार छोड़े (अकेले सुख की चाह में संयुक्त परिवार)।

अब कोई रीति या परंपरा बची है? ऊपर से नीचे तक गौर करो, तुम कहां पर हिन्दू हो, भारतीय हो, सनातनी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कुछ और हो!

कहीं पर भी उंगली रखकर बता दो कि हमारी परंपरा को मैंने ऐसे जीवित रखा है।

क्या आप जानते हैं?

1. बौद्धों ने कभी सर मुंड़ाना नहीं छोड़ा!
2. सिक्खों ने भी सदैव पगड़ी का पालन किया!
3. मुसलमानों ने न दाढ़ी छोड़ी और न ही 5 बार नमाज पढ़ना!
4. ईसाई भी संडे को चर्च जरूर जाता है!

फिर हिन्दू अपनी

1. पहचान-संस्कारों से क्यों दूर हुआ?
2. कहाँ लुप्त हो गयी- गुरुकुल की शिखा, यज्ञ, शस्त्र-शास्त्र, नित्य मंदिर जाने का संस्कार?
3. हम अपने संस्कारों से विमुख हुए, इसी कारण हम विलुप्त हो रहे हैं।
4. अपनी पहचान बनाओ!
5. अपने मूल-संस्कारों को अपनाओ!!!

Representatives of RWAs under Sub Division Patel Nagar are requested to attend the venue tomorrow well in time to collect/receive electric heaters for RWAs/Security guards.

DSIIDC

You are cordially invited
on the occasion of

Distribution of Electric Heaters to RWA/Security Guards:

DSIIDC's CSR Initiative for Pollution Control

Chief Guest
Smt. Rekha Gupta
Hon'ble Chief Minister of Delhi

Presided by
Sardar Manjinder Singh Sirsa
Hon'ble Minister of Environment & Industries, GNCTD

Venue : Amphitheatre, Delhi Haat Pitampura
Date : 22nd November, 2025 • 8.30 AM

Deptt. of Revenue, GNCTD

DSIIDC, Undertaking of GNCTD

एक मुखी रुद्राक्ष के सेहतवर्द्धक लाभ सामाजिक परिबारिक आर्थिक लाभ वास्तु दोष निवारण अनेको खूबियों वाला

एक मुखी रुद्राक्ष के सेहतवर्द्धक लाभ

1. • इस रुद्राक्ष को धारण करने के 7 दिन बाद ही माइग्रेन में आराम मिलता है।
2. • डिप्रेशन, तनाव और बेचैनी जैसी मानसिक व्याधियों से एक मुखी रुद्राक्ष बचाता है।
3. • न्यूररोटिक डिसऑर्डर से सुरक्षा।
4. • मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है।
5. • इशान कौण वास्तु दोष निवारण में अतिलाभदायक
6. • लक्ष्मी विशेष रूप से विराजती
7. • सर्वोत्तम, सर्वमनोकामना सिद्धि, फलदायक और मोक्षदाता है।
8. • गल्ले में रखने से गल्ला कभी धन से खाली नहीं

9. • एक मुखी रुद्राक्ष की माला को धारण करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक इच्छाएँ पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है
10. • इस रुद्राक्ष के प्रभाव से जीवन में समृद्धि आती है
11. • जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि तथा व्यक्तित्व का विकास होता है
12. • एक मुखी रुद्राक्ष करियर तथा व्यवसाय में सफलता दिलाने में सहायक होता है
13. • एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को आर्थिक लाभ और समाज में मान-सम्मान प्राप्त होता है
14. • यदि कोई व्यक्ति यह रुद्राक्ष धारण करता है तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है
15. • यदि कोई व्यक्ति रक्त, हृदय, आँख और सिर आदि से संबंधित विकार से पीड़ित है तो उसके लिए यह रुद्राक्ष चमत्कारिक उपाय है
16. • यह रुद्राक्ष बुरी आदतों (नशीले पदार्थ का सेवन आदि) को छुड़वाने में सहायक है

कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन शांत हो जाता है। घर में धन का आगमन भी होने लगता है। शरीर में हाई 'बीपी' इसके धारण करने से धीरे-धीरे नियंत्रित होने लगता है। वहीं शत्रु अपनी शत्रुता छोड़ देता है।

पीपल की पूजा करने से क्यों मिट जाता है शनि का प्रकोप?

जब किसी इंसान पर शनिदेव की महादशा चल रही होती है तो उसे पीपल की पूजा का उपाय जरूर बताया जाता है। कई बार मन में यह सवाल उठता है कि ब्रम्हांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि का क्रोध मात्र पीपल वृक्ष की पूजा करने से कैसे शान्त हो जाता है।

आज हम आपको बताने जा रहे हैं शनि और पीपल से सम्बंधित वह पौराणिक कथा जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो।

पुराणों की माने तो एक बार त्रेता युग मे अकाल पड़ गया था। उसी युग मे एक कौशिक मुनि अपने बच्चो के साथ रहते थे। बच्चो का पेट न भरने के कारण मुनि अपने बच्चो को लेकर दूसरे राज्य मे रोज़ी रोटी के लिए जा रहे थे।

रास्ते मे बच्चो का पेट न भरने के कारण मुनि ने एक बच्चे को रास्ते मे ही छोड़ दिया था। बच्चा रोते रोते रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया था तथा पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा था। तथा पीपल के पेड़ के फल खा कर बड़ा होने लगा था। तथा कठिन तपस्या करने लगा था।

एक दिन ऋषि नारद वहाँ से जा रहे थे। नारद जी को उस बच्चे पर दया आ गयी तथा नारद जी ने उस बच्चे को पूरी शिक्षा दी थी तथा विष्णु भगवान की पूजा का विधान बता दिया था।

अब बालक भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा था। एक दिन भगवान विष्णु ने आकर बालक को दर्शन दिये तथा विष्णु भगवान ने कहा कि हे बालक मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप कोई वरदान मांग लो।

बालक ने विष्णु भगवान से सिर्फ भक्ति और योग मांग लिया था। अब बालक उस वरदान को पाकर पीपल के पेड़ के नीचे ही बहुत बड़ा तपस्वी और योगी हो गया था।

एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु हमारे परिवार की यह हालत क्यो हुई है। मेरे पिता ने मुझे भूख के कारण छोड़ दिया था और आजकल वो कहा है।

नारद जी ने कहा बेटा आपका यह हाल शानिमहाराज ने किया है। देखो आकाश मे यह शनैश्चर दिखाई दे रहा है। बालक ने शनैश्चर को उग्र दृष्टि से देखा और क्रोध से उस शनैश्चर को नीचे गिरा दिया। उसके कारण शनैश्चर का पैर टूट गया। और शनि असहाय हो गया था।

शनि का यह हाल देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने सभी देवताओ को शनि का यह हाल दिखाया था। शनि का यह हाल देखकर ब्रम्हा जी भी वहाँ आ गए थे। और बालक से कहा कि मैं ब्रम्हा हूँ आपने बहुत कठिन तप किया है।

आपके परिवार की यह दुर्दशा शनि ने ही की है। आपने शनि को जीत लिया है। आपने पीपल के फल खाकर जीवंन जीया है। इसलिए आज से आपका नाम पिपलाद ऋषि के नाम जाना जाएगा। और आज से जो आपको याद करेगा उसके सात जन्म के पाप नष्ट हो जाएँगे।

तथा पीपल की पूजा करने से आज के बाद शनि कभी कष्ट नहीं देगा। ब्रम्हा जी ने पिपलाद बालक को कहा कि अब आप इस शनि को आकाश मे स्थापित कर दो। बालक ने शनि को ब्रम्हाण्ड मे स्थापित कर दिया।

तथा पिपलाद ऋषि ने शनि से यह वायदा लिया कि जो पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उसको आप कभी कष्ट नहीं दोगे। शनैश्चर ने ब्रम्हा जी के सामने यह वायदा ऋषि पिपलाद को दिया था।

उस दिन से यह परंपरा है जो ऋषि पिपलाद को याद करके शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसको शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया और शनि महादशा कष्ट कारी नहीं होती है।

शनि की पूजा और व्रत एक वर्ष तक लगातार करनी चाहिए। शनि कों तिल और सरसो का तेल बहुत पसंद है इसलिए तेल का दान भी शनिवार को करना चाहिए। पूजा करने से तो दुष्ट मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है।

तो फिर शनि क्यो नहीं प्रसन्न होगा? इसलिए शनि की पूजा का विधान तो भगवान ब्रम्हा ने दिया है।

कावेरी के उद्गम के लिए कौआ बन गए गणेशजी: कावेरी कथा

एक बार जम्बूद्वीप के कई क्षेत्रों में ऐसा सूखा पड़ा कि सब कुछ निर्जल हो चला. मनुष्य पशु पक्षी सभी की जान पर बन आई. पानी नहीं होने से सृष्टि पर संकट आ खड़ा हुआ. ऋषि-मुनि और देवता भी दुखी थे. अनर्थ की आशंका देखकर अगस्त्य ऋषि को बड़ी चिंता हुई। मानव जाति की रक्षा का प्रण ले कर वह ब्रह्माजी के पास पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा- आपसे कुछ छिपा तो नहीं है फिर भी कहता हूं कि पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मची हुई है।

अकाल के चलते मानव जाति पर जो संकट आया है वैसा संकट मैंने अभी तक नहीं देखा था. यदि आपने चिंता न की तो जंबूद्वीप का दक्षिण भूभाग तो जन और वनस्पति विहीन हो जायेगी। आपकी रची सृष्टि पर संकट भारी है।

ब्रह्माजी ने कहा- मैं सब समझता हूं. इस सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हारी चिंता से मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही है लेकिन इस संकट के समाधान का मार्ग बहुत कठिन है. यदि कोई कर सके तो मैं निदान बता सकता हूं।

अगस्त्य ने कहा- सृष्टि के कल्याण के लिए जो भी संभव हो मैं वह करने को तैयार हूं, आप मुझे राह बताइए. ब्रह्मा जी ने कहा यदि कैलास पर्वत से कावेरी को भारत भूमि के दक्षिण में ले आया जाए तो इस संकट का निदान हो सकता है।

यह एक दुष्कर कार्य था पर ब्रह्मा जी ने यह कहकर इसे थोड़ा आसान बना दिया कि आपको पूरी नदी नहीं लानी है. बस कैलास की थोड़ी हिम या बर्फ ही अपने कमंडल में लानी होगी. उसी से कावेरी यहां पर स्वयं प्रकट हो जायेंगी।

अगस्त्य मुनि कैलास पर्वत की और चल पड़े. अगस्त्य अपने तपोबल से शीघ्र ही कैलास पर्वत पर जा पहुंचे. बिना देर लगाये अपने कमंडल में कैलास पर्वत की बर्फ भरी और सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण दिशा की ओर लौट चले।

मार्ग में उन्हें ध्यान आया कि शीघ्रतावश ब्रह्माजी से यह पूछना ही भूल गए कि कैलास पर्वत से लाये हिमजल का क्या करना है? कावेरी का उद्गम कहां रहेगा. यह सब विवरण तो पूछा ही नहीं.

वह स्वयं के अनुमान से नदी के उद्गम स्थान की खोज करते हुए कुर्ग क्षेत्र में पहुंचे. कैलास से कमंडल भर कर लाते और उद्गम स्थान की खोज करते-करते ऋषि थक गए. उन्होंने कमंडल को भूमि पर रखा और विश्राम करने लगे. ऋषि थकान उतारने के लिए स्थान तलाशने लगे. पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित सुन्दर ब्रह्माकपाल पर्वत उन्हें दिखाई पड़ा. इस सुंदर पहाड़ के एक कोने में एक छोटा सा जलाशय भी था. अगस्त्य को विश्राम के लिए स्थान उत्तम लगा।

मनोरम स्थल पर विश्राम को बैठे अगस्त्य की झपकी लग गयी. थोड़ी देर में अचानक एक आहट से उनकी तंद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि जो कमंडल कैलाश से भरकर लाए थे वह भूमि पर लुढ़क चुका है. जल बह रहा है और पास ही एक कौवा बैठा है. अगस्त्य तत्काल समझ गये कि यह सब कौवे का किया धरा है. कौवा उड़ते उड़ते आया होगा और जल की अभिलाषा में कमंडल पर बैठा होगा. भूमि समतल न होने से कमंडल असंतुलित हो लुढ़क गया होगा।

जब ऋषि ने यह अनर्थ देखा और अपने संपूर्ण श्रम से ज्यादा मानव जाति की समाप्ति की समस्या के समाधान पर पानी फिरता देखा तो उन्हें कौवे पर अत्यंत क्रोध उमड़ आया।

क्रोध से भरे अगस्त्य कौवे को उसके किए का दंड देने ही वाले थे कि अचानक कौए ने रूप बदला और गणेशजी प्रकट हो गए. अब नतमस्तक होने की बारी ऋषि की थी. गणेशजी ने ऋषि से कहा कि मैं आपके परोपकार की भावना से बहुत प्रभावित हूं।

उद्गम स्थल ढूंढने में आप विलंब न करें. इस प्रक्रिया में न तो आपको ज्यादा श्रम लगे न थकान हो और न ही मानव जाति प्रतीक्षारत रहे. इसलिए कौवे का रूप धारण करके आपकी सहायता के लिए मैं स्वयं आया था।

कावेरी के लिए यही उचित उद्गम है. यह कहने के साथ भगवान गणेश अंतर्धान हो गए. उधर कावेरी की कलकल सुन कर ऋषि भी अत्यधिक प्रसन्न हुए. उनकी थकान लुप्त हो गयी. चूंकि गणेशजी के प्रहार से कमंडल का जल गिरकर पहले एकत्र हुआ और फिर बहा था इसलिए जहां वह जल गिरा था वह तालाब जैसा बन गया. कावेरी वहीं से निकलकर ब्रह्मकपाल पर्वत से प्रवाहित होती है।

मैनपुरी की अमर विभूति : स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मैनपुरी की अमर विभूति स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी न केवल मैनपुरी के अपितु अपने समूचे देश के गौरव थे।इनका जन्म 12 अप्रैल सन्1900 को मैनपुरी जनपद की करहल तहसील के ग्राम चंदीकरा में उस प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था,जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभाई है।इनके पिता का नाम स्व. पण्डित गरुवर सिंह था।इनके अग्रज स्व. पण्डित सिद्धगोपाल चतुर्वेदी "मैनपुरी षड्यंत्र केस" के प्रमुख अभियुक्त रहे थे।इनके सबसे बड़े भाई स्व. पण्डित दीनदयाल चतुर्वेदी ने अपने जीवन का उत्तरार्ध संन्यास ग्रहण कर स्वामी देवानंद सरस्वती के नाम से काशी एवं प्रयागराज में बिताया था। स्यात, अपने परिवार की गौरवशाली परंपराएं उन्हें विरासत में मिली थीं।

स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा चंदीकरा(मैनपुरी) में एवं बाद की शिक्षा मैनपुरी, आगरा व इलाहाबाद में बी.ए. , एल-एल.बी. तक हुई।इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की "विशारद" परीक्षा भी ससम्मान उत्तीर्ण की थी। हिन्दी,अंग्रेजी एवं उर्दू आदि भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। हिन्दी से उन्हें विशेष प्रेम था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हिन्दी परिषद् के मंत्री भी रहे थे।इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नयन हेतु जो अनेकानेक कार्य किए,उनसे प्रभावित होकर वहां के तत्कालीन कुलपति डॉ. गंगानाथ झा ने उन्हें पुरस्कृत भी किया था।विद्या अध्ययन के दौरान उनका विवाह नगला पैज (फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील) निवासी स्व. पण्डित शोभाराम की सुपुत्री गंगादेवी के साथ हो गया था।

सन्1925 में स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी ने मैनपुरी में स्व. बाबू धर्म नारायण,वकील के निर्देशन में वकालत प्रारंभ की। वे बहुत ही कम समय में माल व फौजदारी के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे।वह कई वर्षों तक भारतीय रेलवे, मैनपुरी की नगर पालिका एवं मैनपुरी व सुजरई आदि रियासतों के कानूनी सलाहकार रहे।कालांतर में वह वकील सरकार के पद पर भी जा पहुंचे।इन्होंने वकालत के व्यवसाय में हमेशा अर्थ की जगह न्याय का पोषण किया।गलत एवं झूठे मुकदमों की पैरवी तो वह करते ही नहीं थे।

स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी सन्1935 में कांग्रेस के सदस्य बने और आजीवन बने रहे।वह प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य थे।सेवा समिति,मैनपुरी के द्वारा उन्होंने समाजसेवा के अनेकों कार्य किए।वह मैनपुरी स्काउट सभा के अध्यक्ष व हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन के कमिश्नर दीर्घ काल तक रहे।कई वर्षों तक वे सिविल बार एसोसिएशन एवं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।साथ ही वे उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कई वर्षों तक रहे।वह प्रादेशिक सहकारिता संघ के वरिष्ठ व कर्मठ अधिकारियों में गिने जाते थे।क्योंकि सहकारिता आंदोलन की बुनियाद रखने में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। वे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की एक्जीक्यूटिव कमेटी में कई वर्षों तक पदस्थ रहे।जिला सहकारी बैंक, मैनपुरी के वह लगभग 10 वर्षों तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे।वे मैनपुरी की जिला परिषद् के सन्1936 में चेयरमैन चुने गए थे।इस पद पर उन्होंने 30 अप्रैल सन् 1948 तक निरन्तर 12 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक सहायता आदि देकर अपना हर सम्भव योगदान दिया था।

स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी

स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी ने भयंकर गुलामी के काल में भी राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे,उन्हें राष्ट्र भाषा हिन्दी का इतिहास कभी भी नहीं भुला पाएगा। वे लम्बे अर्से तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन एवं अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मण्डल के प्रधानमंत्री रहे। उनके ही अथक प्रयासों से महाकवि देव की जन्म स्थली कुसमरा (मैनपुरी) में महाकवि देव स्मारक की स्थापना हुई थी।इन्होंने ही सुजरई की रानी के इकलौते पुत्र स्व. लाल सूरज भान सिंह के साहित्य प्रेम को दृष्टिगत रखते हुए मैनपुरी के लेनगंज पार्क में लाल सूरज भान सिंह पुस्तकालय की स्थापना कराई।जिसके कि वो आजीवन मंत्री रहे। वे आगरा कॉलेज,आगरा के लगभग 15 वर्षों तक ट्रस्टी रहे।ब्रिटिश काल में वह एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से भी कई वर्षों तक संबद्ध रहे।इन्होंने ग्राम सुधार संघ, मैनपुरी के द्वारा विभिन्न ग्रामीण अंचलों में समाजसेवा के अनेकानेक कार्य किए। उत्तर प्रदेश की कई शिक्षण व समाजसेवी संस्थाएं उनके ही संरक्षण में पल्लवित हुईं।17 मार्च सन्1960 को उन्होंने "वकील सरकार" के पद से त्यागपत्र देकर एम.एल.ए. व एम.एल.सी. के चुनाव लड़े थे।जिनमें कि वे विभिन्न कारणों से सफल नहीं हो सके।प्रादेशिक सहकारिता संघ की ओर से उनको जून 1963 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डेलीगेशन के अन्तर्गत इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सेमिनार के लिए वारसा (पोलैंड) भेजा गया था। वहां से लौटने पर उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार में एक बहुत बड़े पद पर होने वाली थी, किन्तु दैव दुर्विपाक से 12 अगस्त सन्1963 (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) को उनका आकस्मिक निधन हो गया।

स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी का व्यक्तित्व निर्झरयुक्त भूधर की संज्ञा से उपमित किया जा सकता था।उनका ललाट उन्नत था, दृष्टि विशुद्ध थी, मुख मंडल पर तेज था, वाणी में ओज था, भाव प्रेक्षणीयता थी। सहृदयता, सौजन्यता, स्वाभिमान और निर्भीकता आदि उनके हृदय में गहरी नींव लिए हुए थे। नौजवानों जैसा उत्साह उनमें सदा रहा। सादा जीवन, उच्च विचार का उन्होंने आजीवन पालन किया।वह अत्यधिक मितव्ययी थे। परतंत्रता काल में ही उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया था।वह महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे।वे अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करना पसन्द करते थे।उनकी प्रशंसा वे ब्रिटिश अधिकारी तक करते नहीं थकते थे।जो कि राजनैतिक दृष्टि से उन्हें अपना शत्रु समझते थे।उन्होंने कभी भी किसी से नाजायज पैसा नहीं लिया।साधन व साध्य दोनों की पवित्रता उनके लिए सर्वोपरि थी।उनकी वकालत न्याय व ईमानदारी की वकालत थी।वह बहुत ही संतोषी और विनम्र थे।यदि उन्हें धन से मोह होता तो वे अपने पदों व स्थितियों का दुरुपयोग करके बहुतेरा धन कमा सकते थे,किन्तु उन्होंने ऐसा कभी भी सोचा तक नहीं।उन्होंने अपने गांव की जमीन व मकान आदि अपने कुछ परिवारीजनों को यों ही सौंप दिए थे, जिसकी एवज में उन्होंने उनसे कभी भी कुछ नहीं लिया।ऐसे उदाहरण आज के समय में कहां देखने को मिलते हैं?

स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी की सौम्यता, ईमानदारी, निर्भीकता और न्यायप्रियता आदि सद्गुणों के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे उनके उदात व मानवतावादी दृष्टिकोणों का पता चलता है।मैनपुरी जनपद के लिए उनकी एक नहीं अपितु अनेकों देनें हैं।जिनकी वजह से आगामी पीढ़ियां उन्हें याद करके उन पर गर्व करती रहेंगी।मैनपुरी के करहल रोड़ की और संता-बसंता चौराहा से राजा के बाग तक पक्की सीमेंटेड सड़कें सर्वप्रथम मैनपुरी की जिला परिषद् के द्वारा तब बनवायी गईं थी, जबकि उसके चेयरमैन स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी हुआ करते थे।मैनपुरी की जिला परिषद् की आय बढ़ाने हेतु भी वो सदैव प्रयत्नशील रहे।यमुना नदी के नौरंगी घाट पर टोल टैक्स के रूप आगरा की जिला परिषद् को जो आय होती थी, उसका एक चौथाई भाग स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी के व्यक्तिगत प्रयासों से ही मैनपुरी की जिला परिषद् को मिलना प्रारम्भ हुआ; क्योंकि वो आगरा व मैनपुरी दोनों ही जिलों से जुड़ा हुआ क्षेत्र था।वे जब मैनपुरी की जिला सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक थे, तब वे बैंक के कार्यों से जब भी ट्रेन द्वारा मैनपुरी से बाहर जाते थे तो वे तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे, जबकि वे प्रथम दर्जे में यात्रा करने के अधिकारी थे।प्रादेशिक सहकारिता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने बिना कोई भत्ता या पारिश्रमिक लिए बगैर अपने दायित्वों का निर्वाह किया।मैनपुरी की रियासत "कोर्ट ऑफ वार्ड" से उनके प्रयासों से छूटी थी।

सन्1962 में मैनपुरी के गुरुचरण इंडस्ट्रियल वर्क्स ने अपने सर्वप्रथम राइस प्लांट का निर्माण किया था, किन्तु इस प्लांट को मैनपुरी नगर में कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था।क्योंकि उसकी सफलता पर लोगों को संदेह था।परन्तु स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी ने अपने जय हिंद राइस एण्ड जनरल मिल्स के लिए इस प्लांट को खरीदा और लोगों के संदेह को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त किया।

विडंबना इस बात की है कि इस सब के बावजूद भी स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी की स्मृति-रक्षा हेतु मैनपुरी नगर में अभी तक कहीं भी कोई कार्य नहीं किया गया है।मैनपुरी की जिला परिषद् , जिला सहकारी बैंक, नगर पालिका, लाल सूरज भान सिंह पुस्तकालय, जिला बार एसोसिएशन, एवं सिविल बार एसोसिएशन आदि सभी का यह दायित्व बनता है कि वे स्व. पण्डित सियाराम चतुर्वेदी का समय-समय पर स्मरण कर उनकी स्मृति-रक्षा हेतु कुछ ठोस कार्य करें।जिससे नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके।

सीतामढ़ी में 51 शक्तिपीठों के ज्योत लाएगी रामायण रिसर्च काउंसिल

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। छटीकरा रोड़ स्थित होटल किरधा रेजीडेंसी में रामायण रिसर्च काउंसिल, नई दिल्ली के तत्वावधान में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई जिसमें मां सीताजी के प्राकट्य क्षेत्र सीतामढ़ी में 51 शक्ति पीठों से मिट्टी एवं ज्योत लाकर सीतामढ़ी को तीर्थ एवं शक्ति क्षेत्र के रूप में विकसित करने संबंधी संकल्प पर चर्चा हुई।

कार्यक्रम के प्रारंभ में संचालन कर रहे सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी एवं काउंसिल के ट्रस्टी देव दत्त शर्मा ने सभी संतों को काउंसिल के विभिन्न प्रकल्पों एवं सीतामढ़ी में काउंसिल के क्रियाकलापों की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने काउंसिल को लगभग 12 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। जिस पर एक शक्तिपुंज के रूप में ज्योत स्थापित होगी।

उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी स्थित श्रीराम जानकी स्थान पर हनुमानजी के 108 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ जटायुजी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा एवं धनुष की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।

श्रीउमाशक्ति पीठाधीश्वर स्वामी रामदेवानन्द सरस्वती महाराज एवं सन्त प्रवर स्वामी गोविंदानंद तीर्थ ने कहा कि सनातन धर्म के प्राचीन सिद्ध स्थलों का संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए सभी सनातनियों को तन-मन-धन से सहयोग करना होगा।

प्रख्यात साहित्यकार रूपी रत्न डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टी देवदत्त शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ और कर्मठ अधिकारी रहे हैं। उनके द्वारा रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, वे अति प्रसंशनीय हैं। हम सभी को उनका तन, मन और धन से सहयोग करना चाहिए।

प्रमुख समाज सेविका प्रोफेसर (डॉ.) लक्ष्मी गौतम ने कहा कि वह सीता सखी समिति के अंतर्गत अधिक से अधिक बहनों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगी।

काउंसिल के महासचिव कुमार सुशांत ने कहा कि रामायण रिसर्च काउंसिल इस देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो सीताजी और रामजी पर साथ-साथ कार्य करती है। उन्होंने बताया कि काउंसिल ने अयोध्या में श्रीराममंदिर संघर्ष पर 1250 पृष्ठों का अब तक का सबसे बड़ा ग्रन्थ 'श्रीरामलला- मन से मंदिर तक' भी तैयार कर चुकी है, तो वहीं मां सीताजी के प्राकट्य-

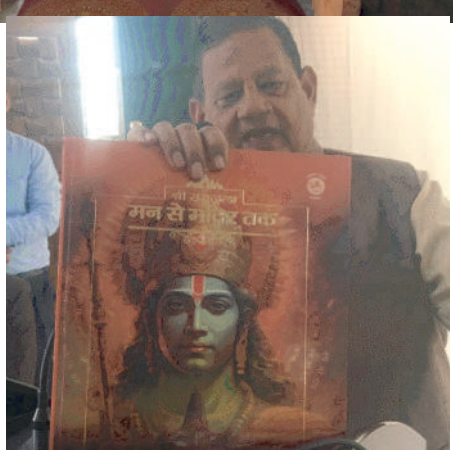

क्षेत्र सीतामढ़ी को भी तीर्थ एवं शक्ति-स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वामी ब्रह्मेन्द्रानन्द सरस्वती महाराज ने कहा कि अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि के लिए भी अभियान यहीं से प्रारंभ हुआ और अब प्रसन्नता है कि जगत जननी मां सीताजी के लिए भी काउंसिल के तत्त्वावधान में अभियान इसी वृंदावन से प्रारंभ हो रहा है।

बैठक में मुख्य वक्ता रहे चतुः संप्रदाय के श्रीमहन्त फूलडोल बिहारीदास महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी सुरेशानन्द परमहंस समन्वयक थे।

भागवत प्रवक्ता आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि वह कथावाचकों को एकजुट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हर कथा में सीता माता के इस विषय की चर्चा हो।

इस अवसर पर महामण्डलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज, महामण्डलेश्वर स्वामी आदित्यनन्द गिरि महाराज, भागवत किंकर अनुराग कृष्ण शास्त्री, महामण्डलेश्वर स्वामी चित्प्रकाशानन्द महाराज, महामण्डलेश्वर नवल गिरि महाराज, स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि महाराज, महन्त सुन्दर दास महाराज, स्वामी कौशलेंद्रानन्द महाराज, स्वामी माधवानन्द महाराज, आचार्य आशुतोष चैतन्य, स्वामी शिवचंद्रानन्द महाराज, स्वामी परमानन्द सरस्वती, आचार्य हरिहर मुद्गल, स्वामी कमलेशानन्द सरस्वती महाराज, स्वामी अद्वैत मुनि, प्रमुख समाज सेवी कपिल देव उपाध्याय, पण्डित आर.एन. द्विवेदी (राजू भैया), आचार्य मोहित कृष्ण शास्त्री, आचार्य सुमंत कृष्ण शास्त्री, भागवत विदुषी श्रीहरि वर्षा कौशल, कपिल उपाध्याय, पूर्व सी.डी.ओ. राधे श्याम गौतम, डॉ. राधाकांत शर्मा, महन्त लाडिली दास, जोगिन्द्र सिंह प्रजापति, पण्डित ध्रुव शर्मा, योगेंद्र शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस कार्यक्रम के लिए प्रख्यात श्रीराम कथा मर्मज्ञ सन्त विजय कौशल महाराज, महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज, श्रीनाभापीठाधीश्वर स्वामी सुतीक्ष्ण देवाचार्य महाराज, श्रीपीपाद्वाराचार्य जगद्गुरु बलरामदास देवाचार्य महाराज, सन्त सियाराम बाबा महाराज (गोवर्धन), ब्रह्मर्षि स्वामी देवदास महाराज (बड़े सरकार), भागवताचार्य डॉ. संजीव कृष्ण शास्त्री, डॉ. संजय कृष्ण सलिल, सन्त प्रवर टाट बाबा महाराज, बाबा सन्त दास महाराज, सन्त महेशानंद सरस्वती महाराज आदि ने अपनी शुभकामनाओं के द्वारा अपना आशीर्वाद प्रदान किया। संचालन देवदत्त शर्मा ने किया। बैठक का विश्राम स्वरुचि पूर्ण प्रीति भोज के साथ हुआ।

भारतीय मजदूर संघ ने चारों श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन का स्वागत किया:

माननीय प्रधानमंत्री एवं श्रम मंत्री का किया आभार व्यक्त

परिवहन विशेष न्यूज, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) भारत सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता है. जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लंबे समय से प्रतीक्षित चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। ये संहिताएँ देश के समस्त श्रमिक वर्ग को गरिमा, सुरक्षा और उन्नत कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

आज बीएमएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुखलाल मंडाविया जी से भेंट की और श्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा, जिसमें श्रम संहिताओं से जुड़े कुछ मुख्य चिंताएँ भी शामिल थीं। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय मज़दूर संघ (BMS) द्वारा उठाये गए सभी वास्तविक चिंताओं का गंभीरता से समाधान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संसद में संशोधन लाने सहित उचित कदम उठाए जाएँगे। हम श्रम मंत्री के सकारात्मक, संवेदनशील और रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए उनका विशेष धन्यवाद करते हैं।

चारों श्रम संहिताएँ श्रम बाज़ार की नई और उभरती वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए रूपांतरित की गई हैं। निर्धारित रोजगार की सीमाओं से आगे वेतन कवरेज का विस्तार तथा असंगठित एवं नव-विकसित क्षेत्रों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना आधुनिक कार्यबल की आकांक्षाओं के अनुरूप दूरदर्शी सुधारों को दर्शाता है।

बीएमएस पूरे देश में श्रम संहिताओं के प्रभावी और सुगम कार्यान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग देने के प्रति प्रतिबद्ध है। हम सरकार एवं सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद जारी रखेंगे ताकि श्रमिकों का कल्याण श्रम शासन का केंद्रबिंदु बना रहे। बीएमएस का मानना है कि यह भारत की एक न्यायसंगत, समावेशी और सशक्त श्रमिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

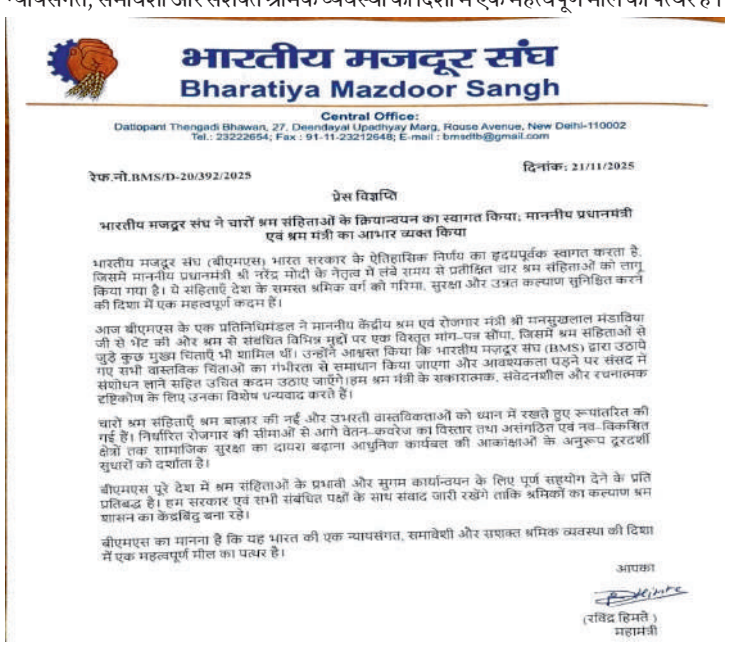

भारतीय मजदूर संघ
Bharatiya Mazdoor Sangh
Central Office:
Dattopant Thengadi Bhawan, 27, Deendayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Tel.: 23222654; Fax : 91-11-23212648; E-mail : bmsdlb@gmail.com

रेफ.नो.BMS/D-20/392/2025 दिनांक: 21/11/2025

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय मजदूर संघ ने चारों श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन का स्वागत किया; माननीय प्रधानमंत्री एवं श्रम मंत्री का आभार व्यक्त किया

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) भारत सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लंबे समय से प्रतीक्षित चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। ये संहिताएँ देश के समस्त श्रमिक वर्ग को गरिमा, सुरक्षा और उन्नत कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

आज बीएमएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुखलाल मंडाविया जी से भेंट की और श्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत मांग-पत्र सौंपा, जिसमें श्रम संहिताओं से जुड़े कुछ मुख्य चिंताएँ भी शामिल थीं। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय मज़दूर संघ (BMS) द्वारा उठाये गए सभी वास्तविक चिंताओं का गंभीरता से समाधान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संसद में संशोधन लाने सहित उचित कदम उठाए जाएँगे।हम श्रम मंत्री के सकारात्मक, संवेदनशील और रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए उनका विशेष धन्यवाद करते हैं।

चारों श्रम संहिताएँ श्रम बाज़ार की नई और उभरती वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए रूपांतरित की गई हैं। निर्धारित रोजगार की सीमाओं से आगे वेतन-कवरेज का विस्तार तथा असंगठित एवं नव-विकसित क्षेत्रों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना आधुनिक कार्यबल की आकांक्षाओं के अनुरूप दूरदर्शी सुधारों को दर्शाता है।

बीएमएस पूरे देश में श्रम संहिताओं के प्रभावी और सुगम कार्यान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग देने के प्रति प्रतिबद्ध है। हम सरकार एवं सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद जारी रखेंगे ताकि श्रमिकों का कल्याण श्रम शासन का केंद्रबिंदु बना रहे।

बीएमएस का मानना है कि यह भारत की एक न्यायसंगत, समावेशी और सशक्त श्रमिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आपका

(रविंद्र हिमते)
महामंत्री

"यह भीड़ देख रहे हैं आप, यह अबैध घुसपैठिये हैं, जो हमारे देश में सीना छोड़ा करके बरसों से रह रहें थे"

"सभी सुख सुविधा, रोज़गार एवं नौकरियों और जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे और वोट भी डाल रहें थे अब SIR डर से चोरों की तरह भाग रहें हैं"
लेकिन उनके देश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, यह पूरी दुनिया जानती है, जबकि वह हिंदू बैध रूप से रहते हैं।
देशहित में चुनाव आयोग ने कार्बोलिक एसिड डाल दिया है, इसलिए घुसपैठिए सांप की तरह बिल से निकल कर वापस भाग रहे हैं।
जहाँ हर सर झुक जाये वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाये वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमी में युद्ध बहुत है,जो हर जंग जीत जाये वही चुनाव आयोग जैसा सिकंदर है।।
थैंक यू चुनाव आयोग इसी तरह से पूरे देश में घुसपैठियों की सफाई होनी चाहिए जय हिंद।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश में हो रही SIR से ख़ुश होकर आम ग़रीब लोगों ने चुनाव आयोग को धन्यवाद करते हुए कहा कि जहाँ हर सर झुक जाये वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाये वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमी में युद्ध बहुत है,जो हर जंग जीत जाये वही चुनाव आयोग जैसा सिकंदर है। देशहित में चुनाव आयोग ने कार्बोलिक एसिड डाल दिया है, इसलिए घुसपैठिए सांप की तरह बिल से निकल कर वापस भाग रहे हैं। तस्वीरों यह जो भीड़ देख रहे हैं आप, यह अबैध घुसपैठिये हैं। जो हमारे देश में बरसों से अबैध रूप से रह रहें थे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं sir शुरू हुए और हजारों की संख्या में अवैध घुसबैठिए झुकी झोपड़ी खाली करके बैंकों से अपना पैसा निकाल के काम काज़ छोड़कर नौकरी छोड़कर चोरी भाग रहे हैं। बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से पिछले चार दिनों में अपने देश भागने की फिराक में करीब 400 घुसपैठिए पकड़े हैं। वहीं एक महीने में आठ हजार से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। कई तो ऐसे है जिनके पास भारतीय आधार कार्ड, फ़र्ज़ी वोटर, कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस भी है।

उन्होंने आगे कहा कि बताया जाता है कि न्यू टाउन, साल्ट लेक आदि जगहों पर काफी घुसबैठिए रह रहें थे लेकिन अब कुछ लोग ही बचें हैं, कमाल की बात है और शाहिदा स्टेशन पर यह बताया जा रहा है कि 35% आबादी जो है वह घुसपैठियों की ही है। यह लोग हमारे देश में इतने सालों से सीना चौड़ा करके अवैध रूप से रह रहे थे। देश की सभी सुख सुविधा, रोज़गार और नौकरियों का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उनके देश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। यह पूरी दुनिया जानती है, जबकि वह हिंदू बैध रूप वेद रूप से रहते हैं। थैंक यू चुनाव आयोग इसी तरह से पूरे देश में घुसपैठियों की सफाई होनी चाहिए जय हिंद।

उन्होंने बताया कि बड़े तज्जूब की बात हैं। घुसपैठिये सालों से यहां रह रहे हैं, और पिछले चुनाव में फ़र्ज़ी भारतीय बनकर वोट भी डाल चुके हैं और वोटर कार्ड हमारे यहां के रसूखदार नेता व कार्यकर्ता बनवाकर दे देते हैं और यह उन्हीं पार्टियों को जिताने के लिए अपना फ़र्ज़ी वोट देते हैं। अब आप सोचिए के भारत के चुनाव में कितनी बड़ी मिलावट होती है, कितनी बड़े स्तर पर हमारे रसूखदार नेताओं की मिली भगत से कितनी बड़ी वोट चोरी होती है। दूसरे देश के नगरिक अबैध तरीके से हमारे भारत में वोट देते रहे हैं, हमारे देश में ये घुसपैठिये हमारे ही देश के संसाधनों को तो खा ही रहे हैं साथ ही हमारी नौकरियां भी ले रहे हैं, हमारी

जगह भी ले रहे हैं। हमारे हिस्से का खाना भी ले रहे हैं, शिक्षा भी ले रहे हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाएं भी ले रहे हैं और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं और हमारे देश की जमीन भी घर रहे हैं और तो और हमारे देश के चुनाव में विदेशी होकर भी अपना वोट डाल रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अब आप बताइए आपके घर में कोई घुस आए और घुसकर बैठ जाए तो क्या आप चैन से रह सकते हैं। कोई भी आम नागरिक सबसे पहले यह चाहता है कि वो दो वक्त की रोटी खाए और सुकून की नींद सोए लेक़नि जब नींद ही खराब हो जाए तो आम ग़रीब आदमी क्या करेगा कहां जाएगा। अरे भाई जान है तो जान है, अगर जान ही नहीं रही तो इंसान बाकी मुद्दों का करेगा क्या? यह सारे चुनावी मुद्दे अपनी जगह पर है, लेक़नि ज़ब आतंकबड़ी देश में बम करते हैं और निर्दोष लोगों को मारते हैं तो हमारे परिवार और बच्चों को घर से बाहर निकालने में भी डर बना रहता है। क्युकी घुसपेठीये हमारी छाती पर चढ़कर आकर बैठ गए हैं, हम गरीबों से हमारी नौकरी छीन रहे हैं, हमारे रोजगार छीन रहे हैं, और हमारे हक अधिकार चोरी कर रहे हैं और गरीबों को दी जा रही भारत सरकार की सभी सुख सुविधा चुरा रहें हैं और हम को बम धमाका करके आतंकवादी हमको ही मार रहे हैं। यानी हमारा ही खा कर हमें ही मार रहें हैं। ऊपर से घुसपैठियों को बचाने वाले हमारे देश के नेताओं को कुछ हया शर्म नहीं बची हैं। यह सभी तो गठबंधन बनाकर उल्टा घुसपैठियों को बचा रहे हैं। इन्होंने देश को आतंकवाद की आग में झोंक दिया है। घुसपैठियों का और आतंकवादियों का सपोर्ट करके हमारे देश के नेता देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब भारत का ग़रीब आम आदमी क्या करे? ऐसे में ग़रीब आदमी के साथ कौन खड़ा होगा?

आखिर में उन्होंने कहा कि घुसपैठिये देश की सुरक्षा एवं देश के नागरिकों के हक़ हकुकों में भी सेंध लगा रहें हैं और गरीबों के हक़ अधिकार भी चुरा रहें हैं। और आतंकबादी बम्ब धमाके कर के निर्दोष भारतीयों को मार रहें हैं। आज़ की कठिन परिस्तिथि में अब देश की सुरक्षा एवं देश के नागरिकों के हक़ अधिकार और जान माल की सुरक्षा के लिए पुरे देश में सफाई अभियान बहुत ही ज़रूरी हो गया हैं। इस एसआरआर से अब करोड़ों फर्जी वोटरों के नाम कटेंगे। इसलिए गठबंधन के नेताओं और उनके सपोटर्स को अब बहुत परेशानी होने बाली हैं।

सुख का मापदण्ड और भारतीय यथार्थ

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट की सीमाएँ और भारत में सहानुभूति–ढाँचे की अनिवार्यता

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट में भारत की निम्न रैंकिंग अक्सर वास्तविक कल्याण स्थिति से अधिक सांस्कृतिक तथा धारणा-आधारित पूर्वाग्रहों को दर्शाती है। सुख मापने की पद्धति में निहित सीमाओं को समझते हुए भारत को अपने सामाजिक, संवेदनात्मक और सामुदायिक ढाँचे में सहानुभूति-आधारित सुधारों को बढ़ाना चाहिए।

--- डॉ. सत्यवान सौरभ

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट हर वर्ष किसी देश की सुख-संतुष्टि का आकलन प्रस्तुत करती है। किंतु भारत जैसे विशाल, विविध और सांस्कृतिक रूप से जटिल देश के लिए यह रिपोर्ट कई बार उस यथार्थ को उजागर नहीं कर पाती जो समाज के भीतर गहरे स्तर पर मौजूद है। भारत की रैंकिंग अक्सर सौ से ऊपर दिखाई देती है, जबकि इसी अवधि में भारत ने स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, संरचनात्मक सुधारों और गरीबी कमी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। यह विरोधाभास एक नैसर्गिक प्रश्न खड़ा करता है—क्या किसी देश के "सुख" को केवल सर्वेक्षण-आधारित दृष्टिकोण से समझा जा सकता है? और क्या यह मापन भारतीय जीवन-मूल्यों और सामाजिक वास्तविकताओं को पकड़ने में सक्षम है?

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट का आधार मुख्यतः स्व-आकलन है। सर्वेक्षणकर्ता उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि वे जीवन को दस-स्तरीय सीढ़ी में कहाँ रखते हैं। यह "सीढ़ी-संबंधी मूल्यांकन" पश्चिमी मनोविज्ञान में प्रयुक्त उस विचार पर आधारित है जिसमें सुख को व्यक्तिगत प्राप्तियों और परिस्थितियों के आधार पर मापा जाता है। परन्तु भारतीय समाज में सुख की अवधारणा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामुदायिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक आयामों से भी गहराई से जुड़ी होती है। भारतीय संस्कृति में संतोष, कर्तव्य, परस्पर सहायता, संबंधों की स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन भी सुख का महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। इसलिए जब एक भारतीय उत्तरदाता से पूछा जाता है कि वह दस में से अपने जीवन को कितने अंक देगा, तो उसके भीतर कई सांस्कृतिक कारक सक्रिय होते हैं—विनम्रता, शांत-स्वीकृति, परिस्थिति को भाग्य-नियति से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति, या समाज में शिकायत दिखाने से बचना। इसके परिणामस्वरूप अनेक भारतीय अपने जीवन को कम अंक दे सकते हैं, भले ही वे वस्तुतः अनेक स्तरों पर बेहतर स्थिति में हों।

सर्वेक्षण का नमूना आकार भी भारत के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले, शहरी और ग्रामीण विविधताओं से भरे देश के लिए मात्र लगभग एक हज़ार लोगों के उत्तर पर आधारित निष्कर्ष असंतुलित हो सकते हैं। भारतीय समाज क्षेत्रीय, भाषायी, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों पर अत्यंत विषम है; एक छोटे नमूने का उपयोग करके उस विविधता का प्रतिनिधित्व संभव नहीं। एक जिले के ग्रामीण किसान की जीवन-संतुष्टि की अवधारणा दिल्ली के शहरी पेशेवर व्यक्ति से भिन्न हो सकती है। फिर भी, दोनों को समान पैमाने पर रखकर किसी राष्ट्रीय "सुख-अंक" की व्याख्या करना वैज्ञानिक रूप से सीमित प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में प्रयुक्त सुख की अवधारणा भी सांस्कृतिक पक्षपात से प्रभावित है। पश्चिमी ढाँचा सुख को भौतिक उपलब्धियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष संतुष्टि से जोड़ता है, जबकि भारतीय समाज में अनेक बार सुख का अर्थ कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना,

भावनात्मक सहारा, सामुदायिक सहयोग या आध्यात्मिक शांति से भी जुड़ा होता है। यह अंतर सर्वेक्षणकर्ता की भाषा, शैली, शब्दों और उत्तरदाता के मनोभाव को प्रभावित करता है। अक्सर यह देखा गया है कि भारत के ग्रामीण या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में उत्तरदाता "जीवन के अंक" को किसी ऐसे प्रश्न की तरह स्वीकार करते हैं जिसमें शिकायत या असंतोष दिखाना उचित नहीं लगता। इसी वजह से कई भारतीय वास्तविक अनुभव होने के बावजूद संतुष्टि को अपेक्षाकृत कम आंकते हैं, जिससे परिणाम और अधिक विकृत होते हैं।

इसके विपरीत, भारत ने बीते वर्षों में सामाजिक कल्याण में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। करोड़ों लोगों तक निःशुल्क खाद्यान्न पहुँचाना, सर्वजन स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों में विस्तार, शिक्षा तथा महिला-शिशु पोषण कार्यक्रमों में बढोत्तरी—ये सब समग्र जीवन-गुणवत्ता को बढ़ाने वाले उपाय रहे हैं। किन्तु अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें इन संकेतकों को केवल सीमित रूप से जोड़ती हैं, क्योंकि उनका मूल केंद्र "अनुभूत संतुष्टि" पर आधारित है, न कि "वस्तुनिष्ठ कल्याण" पर। यही कारण है कि वस्तुनिष्ठ रूप से बेहतर होती सुविधाएँ भी रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से उजागर नहीं हो पातीं। भारत में गरीबी में कमी और स्वास्थ्य-सेवाओं की पहुँच में वृद्धि ने जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाया है, परन्तु सुख-सर्वेक्षण इस सकारात्मक परिवर्तन को मापने में अक्षम रहते हैं।

ऐसे में, प्रश्न यह उठता है कि भारत को अपने भीतर ऐसा क्या बदलना चाहिए जिससे समाज अधिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित, सहानुभूतिपूर्ण और संतुलित बन सके। इसका उत्तर "सहानुभूति संरचना"—एक व्यापक सामाजिक ढाँचा है जिसमें राज्य, समाज, संस्थान और समुदाय मिलकर नागरिकों को भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक सहारा, संवाद और सहायता प्रदान करें। इस ढाँचे का पहला स्तंभ मानसिक-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। भारत में मानसिक-स्वास्थ्य को लेकर अभी भी कई भ्रम और कलंक मौजूद हैं। लोग सहायता लेने में संकोच करते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा ढाँचे में मानसिक स्वास्थ्य की अनुपस्थिति समस्या को बढ़ाती है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित परामर्शदाता हों, दूरभाष-आधारित सेवाएँ व्यापक हों और विद्यालयों-कॉलेजों में मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध हो, तो समाज में भावनात्मक असुरक्षा घट सकती है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समुदाय-आधारित सहयोग है। भारतीय संस्कृति में पड़ोस, परिवार और सामाजिक संबंधों की शक्ति अत्यधिक रही है, परन्तु शहरीकरण और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के कारण यह संरचना कमजोर हो रही है। यदि स्थानीय समुदायों में संवाद-चक्र, सहारा-समूह, वरिष्ठ नागरिक सहायता-केंद्र, महिलाओं के लिए सुरक्षित समुदाय-स्थल और युवाओं के लिए साझा सहयोग मंच विकसित किए जाएँ, तो सामाजिक एकांत कम हो सकता है। सहानुभूति तभी विकसित होती है जब लोग एक-दूसरे के जीवन में उपस्थिति का अनुभव करें।

सहानुभूति संरचना का तीसरा स्तंभ कार्यस्थल है। कार्यस्थलों पर तनाव, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य-दबाव और असुरक्षा बढ़ रही है, जिसके चलते कर्मचारियों का मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। यदि संस्थान संवेदनशील नीति अपनाएँ—कार्य अवधि में लचीलापन, परामर्श सेवाएँ, साथी-सहयोग कार्यक्रम, नेतृत्व प्रशिक्षण में सहानुभूति-आधारित व्यवहार—तो यह वातावरण को स्वस्थ बना सकता है। एक सहानुभूतिपूर्ण संस्थागत संस्कृति न केवल कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाती है।

चौथा आयाम विद्यालयों में भावनात्मक शिक्षा का है। बच्चों में सहानुभूति, अहिंसक संवाद, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोगात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि बच्चे अपनी भावनाएँ समझना, व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीखें, तो समाज भविष्य में अधिक संवेदनशील बनेगा। शैक्षणिक ढाँचा केवल परीक्षा-आधारित न रहकर जीवन-आधारित होना चाहिए।

पाँचवाँ पक्ष तकनीकी सहारा है। यदि तकनीक का उपयोग मानसिक-स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग के लिए किया जाए—जैसे परामर्श ऐप, संकट में सहायता, छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल संवाद केंद्र—तो यह सहानुभूति संरचना को व्यापक बना सकता है। तकनीक का जिम्मेदार उपयोग सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकता है, बशर्ते उसकी निगरानी और नैतिकता मजबूत हो।

अंततः, राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में भी सहानुभूति की आवश्यकता है। जब सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, परिवहन, सुरक्षा और न्याय-प्रणाली में कार्यरत लोग नागरिकों के प्रति अधिक करुणामय व्यवहार अपनाएँ, तो नागरिक-राज्य संबंध और भी मजबूत होते हैं। जनता की समस्याओं को सुनना, सम्मान देना और समाधान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

इस प्रकार विश्व हैपीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग उसे केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय एक अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए। यह अवसर भारतीय समाज को यह विचार करने का मार्ग देता है कि कैसे हम "सुख" को केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक भरोसा, संवेदनशील संवाद और मानसिक-स्वास्थ्य संरचना के रूप में विकसित कर सकते हैं। रिपोर्ट की पद्धति में चाहे जितनी सीमाएँ हों, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज किस दिशा में जाए। भारत यदि अपनी पारंपरिक सामुदायिक शक्ति को आधुनिक सामाजिक-कल्याण ढाँचे के साथ जोड़ दे, तो सहानुभूति-आधारित विकास की एक नई धारा स्थापित हो सकती है, जो वास्तविक सुख को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

वैश्विक व्यापार में रुपये की नई दस्तक

— स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पहलें

रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत को आर्थिक स्वायत्तता, भुगतान सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इससे डॉलर पर निर्भरता घटती है, भुगतान बाधाएँ कम होती हैं और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटता है। निर्यातकों को विनिमय दर से जुड़े जोखिम कम होते हैं, जबकि व्यापारिक साझेदारों के लिए भी स्थानीय मुद्रा में निपटान अधिक सरल व स्थिर होता है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, त्वरित भुगतान तंत्र की वैश्विक पहुँच, तथा रुपये आधारित ऋण व्यवस्था जैसे कदम भारत को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली भूमिका की ओर अग्रसर करते हैं।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत आज उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण केंद्र बन रहा है और इसी आकांक्षा के साथ वह अपनी मुद्रा—भारतीय रुपये—को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अधिक स्वीकार्य बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। बदलते भू-राजनीतिक वातावरण, डॉलर-निर्भरता से जुड़ी अनिश्चितताओं तथा बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था के उभार ने यह अवसर प्रदान किया है कि भारत क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ाए। इसी संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत और इसे अनेक देशों के साथ लागू करने की कोशिश रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत बनाने वाली निर्णायक पहल बनकर उभरी है।

रुपये के प्रसार के पीछे कई प्रेरक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, क्योंकि डॉलर आधारित भुगतान तंत्र अनेक बार राजनीतिक तनाव, प्रतिबंधों और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के समय जोखिम पैदा करता है। रूस–यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत ने अनुभव किया कि डॉलर आधारित तंत्र के कारण कई लेनदेन बाधित हो जाते हैं और व्यापार प्रभावित होता है। यदि व्यापार सीधे स्थानीय मुद्राओं में हो, तो भुगतान अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर भी अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। साथ ही, कई देश अब अपने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे डॉलर-केंद्रित व्यवस्था धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही है। भारत भी इस परिवर्तनशील प्रवृत्ति का स्वाभाविक हिस्सा है।

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और बढ़ते व्यापारिक संबंध भी रुपये-आधारित निपटान की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत–रूस व्यापार पिछले दो दशकों में कई गुना बढ़ा है, परन्तु इस व्यापार में रुपये का उपयोग सीमित है। मुद्रा-आधारित विकल्प बढ़ने से न केवल व्यापार गति पकड़ता है बल्कि भारतीय निर्यातकों को विनिमय दर के उतार–चढ़ाव और हेजिंग लागत से भी राहत मिलती है। दीर्घकाल में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा भारत की आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का संकेत भी बनती है। भारत के 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 1 खरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य की दिशा में यह एक अनिवार्य कदम माना जा रहा है।

हालाँकि, रुपये के वैश्वीकरण के मार्ग में कई चुनौतियाँ भी हैं। अनेक देशों को अभी भी डॉलर या अपनी स्थानीय मुद्रा अधिक स्थिर विकल्प लगती है। कुछ देशों को रुपये की विनिमय दर की स्थिरता पर भरोसा कम है। व्यापारिक साझेदारों के साथ मूल्य-वृद्धि आधारित वस्तुओं का आदान–प्रदान सीमित होने से भी रुपये के व्यापक प्रयोग की संभावना घटती है। भारतीय निर्यातकों में भी रुपये आधारित निपटान के प्रति जागरूकता कम है, जिसके कारण वे इस विकल्प का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अंतरराष्ट्रीय भुगतान और संदेश प्रणाली की सीमित परस्पर संपर्कता भी रुपये की स्वीकार्यता को धीमा करती है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में देश पारंपरिक वैश्वीकरण संदेश तंत्र पर निर्भर हैं।

इन चुनौतियों के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत अब संयुक्त रूप से सहमत देशों के साथ सीधे रुपये में व्यापार कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मॉरीशस और मालदीव के साथ हुए समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम होगा बल्कि बैंकिंग लागत और भुगतान समय में भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने पड़ोसी देशों के बैंक एवं नागरिकों को रुपये में ऋण देने की अनुमति देकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

भारत ने अपने त्वरित भुगतान तंत्र को कई देशों से जोड़कर एक नई वित्तीय संपर्क व्यवस्था विकसित की है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्वरित भुगतान तंत्र का जुड़ना छोटे व्यापारियों, पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए तत्काल भुगतान को सरल बनाता है, जिससे रुपये की उपयोगिता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ती हैं। इसके साथ ही भारत अपनी वित्तीय संदेश प्रणाली को भी साझेदार देशों की प्रणालियों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे परंपरागत वैश्विक संदेश तंत्र पर निर्भरता कम होगी। यह व्यवस्था भुगतान प्रक्रिया को राजनीतिक तनावों से सुरक्षित रखेगी और रुपये की विश्वसनीयता बढ़ाएगी।

समग्र रूप से रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक आकांक्षा का आधार है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, डिजिटल भुगतान संपर्क, द्विपक्षीय वित्तीय संवाद और निर्यातकों की जागरूकता—ये सभी घटक मिलकर रुपये को वैश्विक व्यापार में अधिक उपयोगी और स्वीकृत मुद्रा बना सकते हैं। चुनौतियाँ अवश्य हैं, परंतु बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के पास अवसर भी विशाल है। यदि भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ आपूर्ति श्रृंखला को गहरा करे, भुगतान तंत्र को सरल बनाए और रुपये की स्थिरता को मजबूत करे, तो आने वाले वर्षों में रुपये की वैश्विक भूमिका निश्चित रूप से विस्तार पाएगी।

बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने खींच दी एक बड़ी लाइन, जिसे छोटा करना आसान नहीं!

कमलेश पांडेय

कभी सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक किशन पटनायक ने कहा था कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, लेकिन बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि कोई लाख चिल्ल-पों मचा ले, परंतु बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए कि बिहार के जागरूक मतदाताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग, सुशासन पसंद और राजनीतिक परिवारवाद के धुर विरोधी नीतीश कुमार का नेतृत्व ही पसंद है।

नीतीश कुमार एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इस बार उन्हें अभूतपूर्व जनादेश मिला है जिससे तमाम कयासों को धत्ता बताकर वे पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। इस प्रकार बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने एक वैसी बड़ी लाइन खींच दी है जिसे छोटा करना उनके सियासी विरोधियों के लिए कतई आसान नहीं है।

हालांकि, अपने इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार गठबंधन बदले हैं, जिसमें बीजेपी और महागठबंधन दोनों के साथ शामिल हुए हैं। वाकई नीतीश कुमार की राजनीति का मूल मंत्र व्यावहारिकता, लचीला गठबंधन और प्रशासनिक सुधार है जिसके चलते वे बिहार की राजनीति के केन्द्रीय पात्र बने हुए हैं।

नीतीश कुमार के राजनीतिक बदलाव मुख्य रूप से सत्ता की भूख, सामाजिक परिवर्तन की इच्छा, गठबंधन रणनीति, और बिहार की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुए हैं, जिन्होंने उन्हें बिहार की प्रमुख राजनीतिक शख्सियत बनाया है। नीतीश कुमार की राजनीति व्यावहारिकता, गठबंधन-केन्द्रित रणनीति और सुशासन के एजेंडे पर आधारित रही है, जहाँ वे विभिन्न दलों के साथ बार-बार गठबंधन बदलते हुए भी कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं।

यही वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार में 'इच्छा शासन' का स्तंभ माना जाता है, और उन्होंने बिहार में सत्ता के महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर नियंत्रण बनाए रखा है। यह सभी तथ्य नीतीश कुमार के राजनीतिक गाम्भीर्य और प्रशासनिक कौशल को दर्शाते हैं, विशेष रूप से बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को दिखाते हैं। इनके प्रमुख फैसले लगातार गठबंधन राजनिति में संतुलन बनाना और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना रहे हैं।

बहरहाल, 2024 में वह बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर एनडीए के तहत मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। उनके राजनीतिक फैसलों में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ कर महागठबंधन में शामिल होना, फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना प्रमुख रहे। उन्होंने अपने प्रशासनिक फैसलों में सत्ता नियंत्रण बनाए रखने के लिए कई बार रणनीति बदली, जैसे गृह मंत्रालय अपने पास रखने का अभियान।

विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, जदयू की सीटें लगभग दोगुनी बढ़ीं और एनडीए को 202 सीटों का बहुमत मिला। इसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में गठबंधन सहयोगियों को संतुलित स्थान देने का निर्णय लिया। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कई बार सरकार भंग की और गठबंधन बदला, जिससे उनकी सियासी मजबूती बनी रही।

देखा जाए तो नीतीश कुमार के प्रमुख राजनीतिक बदलाव उनके राजनीतिक कैरियर में उनके रणनीतिक फैसलों, गठबंधन

परिवर्तन, और समाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप उनके दृष्टिकोण में बदलावों का परिणाम रहे हैं।

इसलिए मुख्य राजनीतिक बदलाव और कारण को हम यहां पर गिना रहे हैं:-

पहला, शुरुआती राजनीति और जेपी आंदोलन से उदयनीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य से शुरू हुआ, और उन्होंने अपने शुरुआती करियर में समाजवादी विचारधारा को अपनाया। 1990 के दशक में उन्होंने जनता पार्टी / जनता दल के साथ मिलकर लोकशिक्षा व सामाजिक बदलाव पर फोकस किया।

दूसरा, पहली बार मुख्यमंत्री बनना (2000): तत्कालीन और भौतिक राजनीतिक माहौल में बिहार में शांति व विकास के रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन मात्र 7 दिनों के लिए सीएम बने थे।

तीसरा, महागठबंधन बनाम भाजपा समर्थक नीतिः 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ सरकार से अलग हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सामाजिक-आर्थिक एजेंडे पर भाजपा की नीतियों में बाधाएँ आ रहीं हैं। इसके बाद, उन्होंने जदयू को महागठबंधन, विशेष रूप से राजद (लालू प्रसाद यादव) के साथ शामिल किया, जो उनकी राजनीतिक रणनीति में बड़ा बदलाव था।

चतुर्थ, भाजपा के साथ फिर से संधि और वापस सरकार में आनाः 2017 में, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसका मुख्य कारण सत्ता का स्थायित्व और बिहार में राजनीतिक स्थिरता था। इस निर्णय का कारण उनके दिल्ली और बिहार में होने वाले राजनीतिक दबाव, गठबंधन की राजनीतिक स्थिति, और बिहार में विकास की जरूरतें मानी जाती हैं।

पंचम, समाजिक सुधार और प्रशासनिक बदलावः व्यक्तिगत व्यवहार में सुधार, सामाजिक बदलाव, और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना उनके बदलाव का एक अहम पहलू रहा है, जिससे वे समाज में अपनी छवि को मजबूत करते गए हैं। कारणः राजनीतिक मजबूरियां, सत्ता बनाए रखना, सामाजिक आधार का विस्तार, और बिहार की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों ने उनके इन बदलावों को प्रेरित किया। भीड़-भाड़ वाले पहले गठबंधन से संवाद और वफादारी की कमी, और सियासी विकल्पों का ढलान, उन्हें नए राजनीतिक समीकरण बनाने पर मजबूर किया।

नीतीश कुमार के प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले एवं उनकी नीतियां निम्नलिखित हैं:

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की विकास नीतियों का प्रभाव समग्र रूप से सकारात्मक और व्यापक रहा है। उन्होंने 'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांत पर काम करते हुए राज्य के विकास के पहिये को तेजी से घुमाया है, खासकर समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। इससे बिहार राज्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

उनकी पॉलिसियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, जैसे गांवों को जोड़ना, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, और योजना लाभों का व्यापक वितरण हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर जन-केंद्रित नीतियों और पारदर्शिता के उपायों से भ्रष्टाचार कम करने और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिली है।

आर्थिक दृष्टिकोण से, बिहार ने खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था के अलावा उद्योग और सेवा क्षेत्रों में भी विकास का रास्ता अपनाया है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। जीएसटी जैसे सुधारों का समर्थन कर राज्य ने वित्तीय अनुशासन बनाया और बहुआयामी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा है। हालांकि बिहार लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी की चुनौतियों से जूझता रहा, नीतीश कुमार की सरकारों ने इसे दूर करने के लिए कई सुधार लागू किए जिनका असर अब दिखने लगा है।

आज बिहार में सड़क निर्माण, सिंचाई योजनाओं और सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की गति तेज हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है, और राज्य वर्तमान में विकास एवं आत्मनिर्भरता के पथ पर प्रभावी रूप से अग्रसर है। यह प्रभाव 2025 में भी चुनाव परिणामों और विकास परियोजनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है।

नीतीश कुमार की सियासत को समझने के लिए निम्नलिखित कुछ पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है:-

पहला, गठबंधन आधारित राजनीतिः नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में भाजपा (NDA), राजद-कांग्रेस (महागठबंधन) और अन्य दलों के साथ कई बार गठबंधन बदले हैं। वे जिस भी खेमे में जाते हैं, वहाँ सत्ता का केंद्र बन जाते हैं और सरकार बना लेते हैं; इसका उद्देश्य सत्ता में बने रहना और अपनी पार्टी की प्रासंगिकता बनाए रखना है।

दूसरा, सुशासन और सामाजिक न्यायः उनकी छवि 'सुशासन बाबू' की रही है, जहाँ कानून व्यवस्था, महिलाओं के सशक्तिकरण, पब्लिक सर्विस डिलीवरी व सामाजिक-आर्थिक विकास पर बल दिया गया। पंचायत चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण, महिला आरक्षण और कानून व्यवस्था के लिए तेज रिफॉर्म लागू किए। आधारभूत ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और अमल उनकी मुख्य उपलब्धियां हैं।

तीसरा, विचारधारा और नेतृत्व शैलीः नीतीश समाजवादी विचारधारा से निकले नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीति जमीनी समझ, समय के अनुसार रणनीति बदलने और वास्तविकता पर टिकी है। विपक्ष की तुलना में वे लचीले, समन्वयकारी और हमेशा प्रासंगिक बने रहने को प्राथमिकता देते हैं।

यही नहीं, अपने शासन में उन्होंने बिहार में विकास योजनाओं पर जोर दिया है और संविदाकर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जैसी पहल की है। प्रशासनिक स्तर पर अपनी कैबिनेट का आकार छोटा रखा है लेकिन भविष्य में विस्तार की बात कही है और मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जिम्मेदारी देने का संकेत दिया है।

नीतीश कुमार की राजनीतिक चालाकी और गठबंधन प्रबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर कई बार बनाए रखा, साथ ही भाजपा के लिए बिहार में सत्ता की मजबूती का रास्ता खोला। दोनों के बीच संतुलन बना रहना बिहार की राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक माना जाता है।इस तरह, नीतीश कुमार का सुशासन और सामाजिक गठबंधन पर जोर और भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व वाली मजबूत संगठनात्मक रणनीति ने बिहार में सामूहिक चुनावी सफलता और राज्यों में सत्ता की स्थिरता सुनिश्चित की है।

सच कहूं तो भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति और लाभ बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। नीतीश कुमार की रणनीति में सबसे प्रमुख था 'सुशासन' का एजेंडा, जो 2005 से लेकर अब तक उनके राजनीतिक अभियान की पहचान बना। उन्होंने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, और सामाजिक कल्याण पर जोर देकर खुद को एक सुदृढ़ और भरोसेमंद प्रशासक के रूप में स्थापित किया।

उनके समय में जातीय गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीति को सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और गैर-यादव OBC समुदायों को मुख्य आधार बनाया गया। नीतीश कुमार ने गठबंधन राजनीति में लचीलापन दिखाते हुए बीजेपी और महागठबंधन के बीच अपनी पार्टी के हितो की रक्षा की, जिसे राजनीतिक चतुराई के तौर पर देखा जाता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार में मोदी-नीतीश की जोड़ी को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाया। भाजपा ने गठबंधन सहयोगियों को मजबूत किया और बूथ प्रबंधन से लेकर प्रचार तक कड़े रणनीतिक कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास एजेंडा का समुचित इस्तेमाल कर भाजपा ने बिहार में मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाई। भाजपा ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता दी, जिससे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। गठबंधन में तालमेल बनाए रखने की क्षमता भाजपा की बड़ी जीत का कारण रही।

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक

समस्या बढ़ाती सुंदर दिखने की चाहत

डॉ. विजय गर्ग

एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी और तमाम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का बाज़ार खरबों रुपये का हो चुका है। कंपनियां लगातार यह संदेश देती हैं कि आप वैसे ही सुंदर नहीं हैं जैसा आपको होना चाहिए, और उनकी मदद से ही यह संभव है।
कई समाजों में, खासकर महिलाओं के लिए, सुंदर दिखना सफलता और स्वीकार्यता का पैमाना बन गया है। सुंदरता को अक्सर उनके वास्तविक गुणों और क्षमताओं से ऊपर रखा जाता है।

आज की दुनिया में "सुंदर दिखना" सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि मानो एक दबाव बन गया है। सोशल मीडिया के फ़िल्टर, ग्लैमर इंडस्ट्री के मानक, और समाज की अवास्तविक अपेक्षाएँ—इन सबने मिलकर सौंदर्य को एक प्रतिस्पर्धा में बदल दिया है। परिणाम? सुंदर दिखने की चाहत अब कई बड़ी समस्याएँ पैदा कर रही है—मन में, शरीर में, और पूरे समाज में।

1. सौंदर्य का बदलता अर्थ

कभी सौंदर्य का मतलब था स्वाभाविकता, सरलता और व्यक्तित्व।

अब सौंदर्य मापा जाने लगा है:

गोरे रंग से
पतली कमर से
तीखे नैन-नक्श से
मेकअप और फ़िल्टर से
फोटोशूट जैसी लाइफस्टाइल से

इस नकली "परफेक्शन" की दौड़ ने युवाओं में खतरनाक मानसिक दबाव पैदा किया है।

2. सामाजिक दबाव और तुलना का ज़हर

(1) सोशल मीडिया का प्रभाव

इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और रील्स ने चेहरों को इतना बदला है कि लोग अपने असली रूप को ही कमतर समझने लगे हैं।

हर फोटो में "परफेक्ट" दिखने के दबाव ने तुलना को बढ़ाया और आत्मविश्वास को कम किया।

(2) समाज की टिप्पणियाँ

"इतने दुबले क्यों हो?"
"गोरी होती तो और सुंदर लगती।"
"थोड़ा मेकअप कर लिया करो।"

ऐसी बातें धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्स बना देती हैं।

3. जब सुंदर दिखने की चाहत शरीर को नुकसान पहुँचाती है

(1) कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का अत्यधिक उपयोग

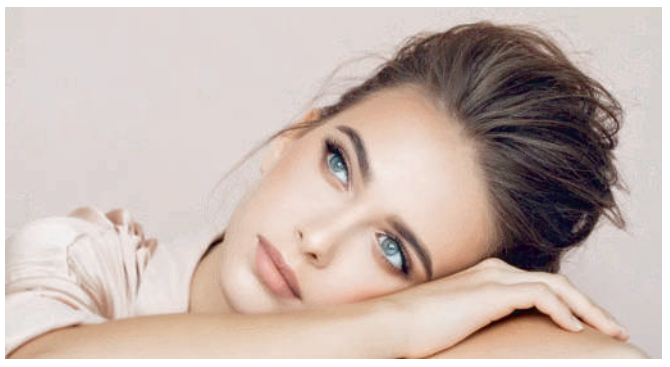

क्रीम, सीरम, त्वचा गोरी करने वाले प्रोडक्ट्स, केमिकल ट्रीटमेंट—

इनमें मौजूद स्टेरॉयड, हाइड्रोक्विनोन, मेलाक्विन जैसे तत्व त्वचा को स्थायी रूप से खराब कर सकते हैं।

(2) वजन घटाने की गलत दौड़

कई युवा
पाउडर शेक
फैट बर्नर
बिना सलाह जिम
का सहारा लेते हैं।

यह हार्मोन असंतुलन, कमजोरी, एनीमिया और मानसिक थकावट का कारण बनता है।

(3) कॉस्मेटिक सर्जरी का बढ़ता चलन

नाक, होंठ, बोटॉक्स, fillers —

इनसे तुरंत सुंदर दिखना संभव है, लेकिन इनके खतरे भी उतने ही गंभीर हैं।

कई युवतियाँ सर्जरी एडिक्शन तक पहुँच जाती हैं।

4. मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर

(1) शरीर के प्रति असंतोष

युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है।

वे अपने असली रूप को स्वीकार ही नहीं कर पाते।

(2) चिंता और अवसाद

सुंदर दिखने की मजबूरी से जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं।

(3) आत्म-सम्मान का गिरना

व्यक्ति का आत्मविश्वास अब उसके "चेहरे" और "फोटो" पर निर्भर होने लगा है, न कि उसके गुणों पर।

यह बहुत खतरनाक बदलाव है।

5. समाज में बढ़ती भेदभाव की प्रवृत्ति

सौंदर्य का यह झूठा पैमाना
नौकरी
रिश्ते
स्कूल

हर क्षेत्र में पक्षपात को जन्म दे रहा है।

गौरवर्ण और पतले शरीर को श्रेष्ठता का प्रतीक बना देना एक सामाजिक अन्याय है।

6. समाधान: सुंदरता नहीं, स्वास्थ्य और आत्म-सम्मान पर ध्यान

(1) प्राकृतिक सुंदरता का मूल्य समझें

सुंदरता चेहरे से नहीं, आत्मविश्वास और स्वभाव से आती है।

(2) शरीर को स्वीकारना सीखें

हर शरीर अलग है—और यही उसकी खूबसूरती है।

(3) सोशल मीडिया की तुलना से दूर रहें

Filter की दुनिया नकली है; वास्तविक दुनिया में पूर्णता नहीं होती।

(4) कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सावधानी

डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी "गोरी करने की क्रीम" या सर्जरी का पीछा न करें।

(5) स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें

संतुलित आहार, नियमित नींद, व्यायाम और पानी—

ये आपको सच में बेहतर बनाते हैं।

क्यों बढ़ रही है यह चाहत?

सोशल मीडिया का प्रभाव: इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर फ़िल्टर और परफेक्ट तस्वीरें एक अवास्तविक दुनिया पेश करती हैं। लोग अपनी तुलना इन आदर्श) छवियों से करने लगते हैं, जिससे उनमें हीन भावना पैदा होती है।

सौंदर्य उद्योग का दबाव: एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी और तमाम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का बाज़ार खरबों रुपये का हो चुका है। कंपनियां लगातार यह संदेश देती हैं कि आप वैसे ही सुंदर नहीं हैं जैसा आपको होना चाहिए, और उनकी मदद से ही यह संभव है।

सांस्कृतिक मानदंड): कई समाजों में, खासकर महिलाओं के लिए, सुंदर दिखना सफलता और स्वीकार्यता का पैमाना बन गया है। सुंदरता को अक्सर उनके वास्तविक गुणों और क्षमताओं से ऊपर रखा जाता है।

समस्या के मुख्य पहलू

सुंदर दिखने की अत्यधिक चाहत कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे रही है:

1. शारीरिक स्वास्थ्य पर खतरा

खतरनाक ब्यूटी ट्रीटमेंट्स: चिर-यौवन की चाहत में लोग बोटॉक्स, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन और अन्य महंगी व संभावित रूप से घातक प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। कई मामलों में इन केमिकल्स के दुष्प्रभाव जानलेवा साबित हुए हैं।

अनैचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल: कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मौजूद हानिकारक रसायन त्वचा और शरीर को लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं।

ईटिंग डिसऑर्डर: 'परफेक्ट' फिगर पाने के लिए लोग भूखे रहते हैं या खतरनाक डाइटिंग करते हैं, जिससे शरीर में पोषण की कमी हो जाती है।

2. मानसिक और भावनात्मक तनाव

आत्म-सम्मान में कमी : जब व्यक्ति स्थापित 'सौंदर्य मानकों' पर खरा नहीं उतर पाता, तो वह खुद को कमतर महसूस करने लगता है।

तनाव और चिंता: लगातार सुंदर दिखने की चिंता, खासकर सार्वजनिक कार्यक्रमों या तस्वीरों के लिए, अनावश्यक मानसिक तनाव पैदा करती है।

डिस्मॉर्फिया): कुछ लोग अपने शरीर के किसी हिस्से को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि उन्हें वह वास्तव में जैसा है, उससे कहीं ज़्यादा बदसूरत नज़र आता है, जो एक गंभीर मानसिक विकार है।

3. आर्थिक बोझ

ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सैलून, जिम मेंबरशिप और कॉस्मेटिक सर्जरी पर भारी खर्च होता है, जो अक्सर व्यक्ति के बजट को बिगाड़ देता है।

✨ समाधान क्या है?

इस समस्या का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर है।

खुद को स्वीकारें: सबसे पहला कदम है खुद को वैसे ही प्यार करना और स्वीकार करना जैसा आप हैं। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा (unique) और खूबसूरत है।

आंतरिक सुंदरता पर ध्यान: अपने ज्ञान, दयालुता, प्रतिभा और अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। चरित्र की सुंदरता किसी भी बाहरी चमक से ज़्यादा स्थायी और आकर्षक होती है।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ: प्राकृतिक सुंदरता के लिए स्वस्थ खान-पान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम सबसे अच्छा 'ब्यूटी रूटीन' है। यह बाहरी दिखावे के बजाय वास्तविक स्वास्थ्य पर केंद्रित होना चाहिए।

मीडिया साक्षरता (Media Literacy): सोशल मीडिया और विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली हर चीज को सच न मानें। याद रखें, वे आपको कुछ बेचने के लिए बनाए गए हैं, न कि आपका आत्म-सम्मान बढ़ाने के लिए।

निष्कर्ष यह है कि सुंदर दिखने की चाहत तब तक हानिकारक नहीं है जब तक कि यह स्वस्थ और प्राकृतिक हो। लेकिन जब यह चाहत एक जुनून बन जाती है और हमें अपनी पहचान, स्वास्थ्य और खुशी से दूर करने लगती है, तो यह स्पष्ट रूप से एक समस्या है। हमें सुंदरता को उसके व्यापक अर्थ में देखना सीखना होगा, जहाँ स्वास्थ्य, आत्म-विश्वास और अच्छा व्यवहार, महंगे मेकअप और सर्जरी से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं।

7. निष्कर्ष

सुंदर दिखने की चाहत गलत नहीं है, लेकिन जब यह चाहत

स्वास्थ्य, आत्म-सम्मान और मानसिक शांति को नुकसान पहुँचाने लगे,

तो यह समस्या बन जाती है।

हमें समाज और सोशल मीडिया द्वारा बनाए नकली सौंदर्य मानकों को चुनौती देनी होगी।

असली सुंदरता वह है जो आपको भीतर से मजबूत बनाए, न कि आपको बदलने या दुख देने लगे।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

शारीरिक परिवर्तन से पता चलेगा कि छात्र तनाव में है या नहीं

डॉ. विजय गर्ग

आज के प्रतिस्पर्धी युग में, छात्रों पर सबसे ज़्यादा दबाव पढ़ाई का है। पढ़ाई, अंक, परीक्षाएँ, करियर की दौड़ और सोशल मीडिया की तुलना - इन सबने बच्चों और युवाओं के मन को बेहद तनावग्रस्त बना दिया है। अक्सर छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, लेकिन शरीर स्वतः ही संकेत देने लगता है कि वे तनाव में हैं।

नीचे कुछ शारीरिक परिवर्तन दिए गए हैं जो यह संकेत दे सकते हैं कि छात्र मानसिक तनाव में हैं।

सिरदर्द और माइग्रेन में वृद्धि

तनाव सबसे पहले सिर को प्रभावित करता है। लगातार सिरदर्द, चक्कर आना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता - ये सभी संकेत हैं कि मस्तिष्क लंबे समय से दबाव में है।

नींद में खलल

तनाव में छात्र
अनिद्रा,
रात में बार-बार जागना,
बुरे सपने,

या बहुत अधिक सोना. इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो आपकी याददाश्त, ध्यान और शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ेगा।

अस्पष्टीकृत थकान और सुस्ती

यदि छात्र ठीक से खा-पी रहे हैं और ठीक से सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अनावश्यक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, तो यह दीर्घकालिक तनाव का संकेत हो सकता है। शरीर लगातार तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का उत्पादन करता है, जो ऊर्जा को कम करता है। 4. पेट की समस्याएं

तनाव का पेट और पाचन तंत्र से सीधा संबंध है। ये लक्षण विशेष रूप से छात्रों में देखे जाते हैं:

भूख न लगना या अत्यधिक भूख लगना
गैस, अम्लता
मल असंयम ये सभी मानसिक दबाव के शारीरिक परिणाम हैं।

तेज़ दिल की धड़कन

तनाव के दौरान हृदय गति बढ़ जाती है। कुछ समय बाद

दिल तेजी से धड़क रहा है,
सीने में भारीपन,
या बेचैन रहो. ये सभी भावनात्मक जलन के लक्षण हैं। 6. कंधों और गर्दन में दर्द

तनाव के समय शरीर स्वतः ही अपनी मांसपेशियों को कस लेता है। गर्दन, कंधे, पीठ और कूल्हे का दर्द छात्रों में बहुत आम समस्या है। समय के साथ, यह दर्द ध्यान और उत्पादकता को बहुत कम कर देता है।

चेहरे पर परिवर्तन - मुँहासे, तैलीय त्वचा, रूखापन

तनाव हार्मोन सीधे झुर्रियों को प्रभावित करते हैं। छात्रों के चेहरे पर अचानक मुंहासे निकल सकते हैं, त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है, या उनका रंग खराब हो सकता है - यह सब तनाव के कारण हो सकता है।

पढ़ाई में रुचि का ह्रास

यद्यपि यह एक मानसिक लक्षण है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। एकाग्रता का अभाव, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा, अनावश्यक रोना, या बार-बार डर महसूस करना. यह छात्र की भावनात्मक थकान का संकेत है।

माता-पिता और शिक्षक क्या कर सकते हैं?

खुलकर बातचीत करें.

छात्र को बताएं कि तनाव महसूस करना गलत नहीं है - लेकिन चुप रहना गलत है।

अपनी दैनिक दिनचर्या को संतुलित रखें।

नींद, आहार, अध्ययन और अवकाश - ये चार चीजें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल अधिभार कम करें

अत्यधिक फोन कॉल और सोशल मीडिया तनाव को दोगुना कर देते हैं।

हल्का व्यायाम, योग, या कोई पसंदीदा गतिविधि

ये मस्तिष्क को एंडोर्फिन रिलीज करने और तनाव कम करने में मदद करते हैं।

पढ़ाई का कोई दबाव नहीं, सहयोग

यदि माता-पिता और शिक्षकों का रवैया सहयोगात्मक हो तो विद्यार्थी अधिक मजबूत बनते हैं।

शरीर कभी झूठ नहीं बोलता. यदि किसी छात्र के शारीरिक परिवर्तन अचानक बढ़ने लगें तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह तनाव में है। वास्तविक आवश्यकता उन्हें समझने, उनके साथ खड़े होने और दबाव कम करने की है। जब तनाव कम हो जाता है तो पढ़ाई में सुधार अपने आप आ जाता है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार

रचनात्मकता की मिसाल है लाइब्रेरी

डॉ विजय गर्ग

लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं होती, यह रचनात्मकता, चिंतन और कल्पना की प्रयोगशाला होती है। एक पुस्तकालय में रखी हर किताब किसी लेखक की सोच, अनुभव और दृष्टि का प्रतीक होती है, जो पाठक के मस्तिष्क को नए विचारों से भर देती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि लाइब्रेरी किसी समाज की बौद्धिक संपदा और उसकी रचनात्मकता का जीवंत प्रतीक है।

लाइब्रेरी का वातावरण मौन होते हुए भी बहुत कुछ कहता है। यहाँ न शोर होता है, न भीड़भाड़, परंतु हर पृष्ठ पलटने के साथ नए विचार जन्म लेते हैं। यह वही स्थान है जहाँ एक विद्यार्थी ज्ञान की खोज में निकलता है, एक लेखक अपने शब्दों की प्रेरणा पाता है और एक विचारक अपनी सोच को आकार देता है।

आज जब डिजिटल युग में सब कुछ मोबाइल और स्क्रीन तक सिमट गया है, तब भी एक लाइब्रेरी की महक, वहाँ की शांति और किताबों से मिलने वाली आत्मीयता का कोई विकल्प नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से अलग होकर खुद से जुड़ता है।

रचनात्मकता का असली अर्थ है—पुराने विचारों में से कुछ नया जन्म देना। लाइब्रेरी यही सिखाती है। अलग-अलग विचारों, लेखकों और युगों की किताबें पढ़ते हुए व्यक्ति अपने भीतर नई सोच और दृष्टि का विकास करता है। यही प्रक्रिया उसे सृजनशील बनाती है।

ज्ञान का केंद्र और विचारों का संगम

पुस्तकालय सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विचारों और संस्कृतियों का संगम स्थल है। हर किताब अपने भीतर एक नया संसार समेटे हुए है। जब कोई पाठक इन किताबों से जुड़ता है, तो वह न केवल लेखक के दृष्टिकोण को समझता है, बल्कि अपने नए विचार भी विकसित करता है।

* प्रेरणा का स्रोत: किताबें पढ़कर व्यक्ति को नई प्रेरणा मिलती है, जो उसे लीक से हटकर सोचने और कुछ नया रचने के लिए प्रोत्साहित करती है।

* विविधता का प्रदर्शन: पुस्तकालयों में साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास जैसे अनेक विषयों

पर पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जो पाठक को अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी देकर उनकी समझ को व्यापक बनाती हैं।

* आज़ादी: यह अपनी मर्ज़ी का पढ़ने और अपनी रफ़्तार से सीखने की आज़ादी देता है, जो रचनात्मक सोच के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

बच्चों में रचनात्मकता का विकास

बच्चों के लिए पुस्तकालय एक प्रयोगशाला के समान है, जहाँ वे किताबों के साथ खेलते हुए सीखते हैं और अपनी रचनात्मकता का विकास करते हैं।

* कहानी रचना: बच्चे किताबों के शीर्षकों या चित्रों से प्रेरित होकर नई कहानियाँ बनाते हैं।

* पढ़ने में रुचि: लाइब्रेरी की गतिविधियों से बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है और वे न सिर्फ पढ़ना सीखते हैं, बल्कि सोचना और सवाल पूछना भी सीखते हैं।

* खुली अलमारी की अवधारणा: कई पुस्तकालयों में किताबें खुली अलमारी में रखी जाती हैं, जिससे बच्चे बिना किसी रोक-टोक के अपनी पसंद की किताब चुन सकते हैं, जो उन्हें स्व-निर्देशित सीखने के लिए प्रेरित करता है।

सामुदायिक सहभागिता और नवाचार

आधुनिक पुस्तकालय अब केवल किताबें इश्यू करने का केंद्र नहीं रहे, बल्कि वे सामुदायिक गतिविधियों और नवाचार को बढ़ावा देने वाले केंद्र बन गए हैं।

* कार्यशालाएँ और कार्यक्रम: पुस्तकालयों में रचनात्मक लेखन, कला, हस्तकला और अन्य कौशल विकास पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं, जो लोगों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का मंच देती हैं।

* सचल पुस्तकालय: कुछ जगहों पर सचल पुस्तकालय भी चलाए जाते हैं, जो उन लोगों तक ज्ञान और रचनात्मकता को पहुँचाते हैं जो पुस्तकालय तक नहीं आ सकते। यह दिखाता है कि रचनात्मकता के प्रसार के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं।

हर समाज की प्रगति के पीछे उसकी पठन संस्कृति होती है। जब बच्चे बचपन से लाइब्रेरी से जुड़ते हैं, तो उनमें कल्पनाशक्ति, तर्कशीलता और संवेदनशीलता विकसित होती है। यही गुण उन्हें एक बेहतर नागरिक और सृजनशील इंसान बनाते हैं।

इसलिए कहा जा सकता है कि लाइब्रेरी केवल किताबों का घर नहीं, बल्कि रचनात्मकता की मिसाल है—जहाँ विचार जन्म लेते हैं, कल्पनाएँ उड़ान भरती हैं और मनुष्य अपनी सोच की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

नए युग के लिए नई कौशल

डॉ. विजय गर्ग

भारत के गहरे प्रौद्योगिकी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग शिक्षा की पुन: कल्पना करना

परिचय: भारत के लिए गहरी तकनीक का क्षण

भारत एक गहरी प्रौद्योगिकी क्रांति के कगार पर है। एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्री जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां अब आला डोमेन नहीं हैं - वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्तंभ बनने की तैयारी में हैं।

हालांकि, जबकि भारत प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक उत्पादन करता है, देश इस प्रतिभा को नवाचार, उच्च अंत अनुसंधान और वैश्विक डीप-टेक नेतृत्व के पावरहाउस में बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है।

डीप-टेक युग में वास्तव में नेतृत्व करने के लिए, भारत की इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली को मूलभूत पुनर्विचार की आवश्यकता है - न कि केवल क्रमिक सुधार।

1। वर्तमान इंजीनियरिंग शिक्षा मॉडल क्यों कम है

ए) सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करें, आवेदन नहीं

भारत में कई इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम काफी सैद्धांतिक बने हुए हैं, जो व्यावहारिक समस्या समाधान पर मूल सीखने पर जोर देते हैं। यह अंतर उन स्नातकों को जन्म देता है जिनके पास उद्योग के लिए तैयार कौशल नहीं हैं, विशेष रूप से AI और डेटा विज्ञान जैसी नई युग प्रौद्योगिकियों में।

बी) कम रोजगार और नवाचार घाटा

हाल के आंकड़ों के अनुसार, केवल लगभग 42.6% भारतीय स्नातक उद्योग मानकों द्वारा रोजगार योग्य माना जाता है। बड़ी संख्या में इंजीनियरों के बावजूद, भारत अभी भी पेटेंट फाइलिंग, कोर डीप-टेक अनुसंधान और मूल तकनीकी सफलताओं के उत्पादन करने में पीछे है।

अकादमिक आउटपुट और वास्तविक दुनिया के नवाचारों के बीच संबंध टूटने का मतलब है कि कई इंजीनियरिंग स्नातक ऐसी भूमिकाओं में समाप्त होते हैं जो उनकी तकनीकी क्षमता का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाते।

क) कमजोर उद्योग - अकादमी संबंध

इंजीनियरिंग कॉलेजों का केवल एक छोटा हिस्सा ही मजबूत उद्योग साझेदारी रखता है।

संकाय सदस्यों को अक्सर अत्याधुनिक उद्योग प्रथाओं के संपर्क में नहीं आता है और वे उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकते हैं।

वास्तविक दुनिया में, परियोजना-आधारित सीखने की कमी है: इंटर्नशिप, व्यावहारिक प्रयोगशालाएं और उद्योग-चालित कैपस्टोन प्रोजेक्ट अभी भी पर्याप्त व्यापक नहीं हैं।

डी) संकीर्ण प्रशिक्षण: अनुशासन सिलो और अंतर-अनुशासनात्मकता की कमी

पारंपरिक इंजीनियरिंग अनुशासन अक्सर कठोर होते हैं: छात्र एक शाखा चुनते हैं और उस पर बने रहते हैं। लेकिन गहरी प्रौद्योगिकी चुनौतियों के लिए अंतर-अनुशासनात्मक सोच की आवश्यकता होती है: इंजीनियरिंग + डेटा विज्ञान + नैतिकता + प्रणाली विचार।

ई) आजीवन शिक्षा पर अपर्याप्त जोर

प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखते हुए, इंजीनियर केवल अपने स्नातक वर्षों के दौरान जो सीखते हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी, कई कार्यक्रम निरंतर अपग्रेड या रीस्किलिंग के लिए तंत्र नहीं बनाते हैं।

नई कौशल भारत को अपने गहरे तकनीकी भविष्य की आवश्यकता है

वर्तमान इंजीनियरिंग प्रतिमान और भविष्य की डीप-टेक दुनिया के बीच अंतर को दूर करने के लिए भारतीय इंजीनियरों को कौशल का एक नया मिश्रण प्राप्त करना होगा

ए) उभरती प्रौद्योगिकियों में तकनीकी तरक्की

एआई और मशीन लर्निंग: न केवल एक ऐड-ऑन के रूप में, बल्कि कोर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के साथ गहराई से एकीकृत।

अर्धचालक इंजीनियरिंग: सामग्री विज्ञान, उपकरण भौतिकी, पैकेजिंग - स्वदेशी चिप बनाने की क्षमता के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण।

आईओटी और रोबोटिक्स: वास्तविक दुनिया, लागू प्रणालियों का डिजाइन - ई-यानत्र स्थानीय समस्याओं के लिए रोबोटिक्स कैसे बना सकते हैं इसका एक शानदार मॉडल है।

साइबर-भौतिक प्रणालियाँ: अनुकूलनशील, लचीली प्रणाली बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कनेक्टिविटी का संयोजन।

बी) सिस्टम्स थिंकिंग और एप्लाइड इंजीनियरिंग

इंजीनियरों को ऐसी प्रणालियों का डिजाइन करना सीखना होगा जो डेटा-आधारित, स्व-लिरीक्षण और अनुकूलन योग्य हों - स्थिर उपकरण नहीं। विशेषज्ञों का तर्क है कि भविष्य के इंजीनियरों को इंजीनियरिंग डिजाइन में वास्तविक समय की प्रतिक्रिया, हेरिस्टिक और पूर्वानुमानात्मक मॉडल शामिल करने में सक्षम होना चाहिए।

ग) अंतर-अनुशासनात्मक और टी आकार के कौशल

टी-आकार के पेशेवर: एक डोमेन में गहरी विशेषज्ञता तथा कई क्षेत्रों में व्यापक साक्षरता - जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा विज्ञान और नैतिकता का संयोजन।

सॉफ्ट कौशल: महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता, सहयोग और संचार - उद्योग 4.0 / इंजीनियरिंग 4.0 वातावरण में सभी आवश्यक हैं।

नैतिकता और सामाजिक जागरूकता: गहरी प्रौद्योगिकी में काम करने वाले इंजीनियरों को समाज के प्रभाव, डेटा गोपनीयता और जिम्मेदार नवाचार को समझना चाहिए।

डी) परियोजना-आधारित अभ्यास

वास्तविक दुनिया की परियोजनाएं, हैकाथॉन, नवाचार चुनौतियां और प्रयोगशाला-आधारित पाठ्यक्रम डिग्री के शुरुआती वर्षों का हिस्सा होना चाहिए।

इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता और सहकारी मॉडल को गहराई से शामिल किया जाना चाहिए ताकि सिद्धांत व्यावहारिक हो सके।

आभासी प्रयोगशालाएं, सिमुलेशन उपकरण और मिश्रित शिक्षा व्यावहारिक अनुभव तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना सकती है।

ई) आजीवन शिक्षा और पुन: कौशल मार्ग

विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को अपने करियर के दौरान इंजीनियरों को उन्नत करने की अनुमति देने के लिए सूक्ष्म प्रमाणपत्र, प्रमाण पत्र और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए।

उद्योग और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी निरंतर सीखने के लिए स्केलेबल मार्ग प्रदान कर सकती है।

f) नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान मानसिकता

डीप-टेक उद्यमिता को प्रोत्साहित करना: छात्रों को न केवल एन के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान मानसिकता

डीप-टेक उद्यमिता को प्रोत्साहित करना: छात्रों को न केवल इंजीनियर के रूप में बल्कि संस्थापक के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए - अर्धचालक, रोबोटिक्स, एआई और उन्नत सामग्रियों में कंपनियों का निर्माण।

अकादमिक जगत में अनुसंधान एवं विकास और पेटेंट संस्कृति को बढ़ावा देना: शोध, आईपी निर्माण तथा उच्च मूल्य वाले नवाचारों को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाना।

विश्वविद्यालय-उद्योग समूह या गहरी प्रौद्योगिकी केंद्र बनाएं जहां अकादमिक क्षेत्र, स्टार्टअप और स्थापित कंपनियां दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी विकास में सह निवेश करें। 3. सुधार और नीति अनिवार्य

इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पर व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता होती है

1। पाठ्यक्रम सुधार

विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को उभरती प्रौद्योगिकियों, प्रणाली सोच, नैतिकता और अंतर-अनुशासनात्मक सीखने को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम पर पुन: काम करना चाहिए।

लचीलापन बढ़ाने के लिए कई निकास/प्रवेश विकल्प, नाबालिग, द्वितीय प्रमुख और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम पेश करें। (कुछ संस्थान पहले से ही ऐसा कर रहे हैं

मजबूत अकादमिक उद्योग सहयोग

इंटर्नशिप, संयुक्त अनुसंधान, नवाचार चुनौतियों और मार्गदर्शन के लिए साझेदारी बनाएं।

कॉलेजों में उद्योग द्वारा वित पोषित प्रयोगशालाओं को सुविधाजनक बनाना ताकि छात्र पेशेवरों के साथ वास्तविक समस्याओं पर काम कर सकें।

संकाय क्षमता निर्माण

परियोजना-आधारित सीखने के लिए गहरी प्रौद्योगिकी (एआई, आईओटी, सेमी, क्वांटम) क्षेत्रों में संकाय प्रशिक्षण में निवेश करें।

प्रोफेसरों को अद्यतन रहने के लिए उद्योग की छुट्टियों को प्रोत्साहित करें, तथा आगंतुक शोधकर्ता कार्यक्रमों को बढ़ावा दें।

डीप-टेक उद्यमिता को बढ़ावा देना

विश्वविद्यालयों में डीप-टेक स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने वाले इनक्यूबेशन केंद्र होना चाहिए।

छात्रों के नेतृत्व वाली डीप-टेक नवाचार कंपनियों के लिए सरकारी प्रोत्साहन (अनुदान, कर लाभ)

निरंतर शिक्षण बुनियादी ढांचा

डिजिटल प्लेटफार्मों, एमओओसी (महाव्यापी ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम) और माइक्रो-क्रेडिटियल का समर्थन करें जिनका उपयोग इंजीनियर अपग्रेड करने के लिए कर सकते हैं।

उद्योग की भर्ती और करियर ग्रगति में ऐसे आजीवन सीखने के क्रेडेंशियल्स को मान्यता देने के लिए नीतिगत ढांचे अपनाएं।

नैतिकता, विविधता और जिम्मेदारी

पाठ्यक्रम में नैतिकता, सामाजिक प्रभाव और जिम्मेदार नवाचार को

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

20 वाँ जी-20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग 21-23 नवंबर 2025 - वैश्विक शक्ति- संतुलन, अमेरिकी अनुपस्थिति और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका का गहन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

जी -20 सम्मेलन में अमेरिका की अनुपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक नेतृत्व अब किसी एक महाशक्ति के हाथ में नहीं

ट्रंप जब वैश्विक सहयोग से दूरी बना रहे हैं, तब मोदी वैश्विक सहयोग को नए स्वरूप में आकार दे रहे हैं।यही विरोधाभास आज की विश्व व्यवस्था का सबसे बड़ा सत्य है-

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख मंच जी-20 इस वर्ष एक ऐसे दौर में बैठक कर रहा है,जब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पहले से कहीं अधिक जटिल, बहुस्तरीय और अनिश्चितता से घिरा हुआ है। 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाला यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है,जब जलवायु परिवर्तन,ऊर्जा संक्रमण,वैश्विक मंदी का खतरा, तकनीकी प्रभुत्व की जंग और भू-राजनीतिक अविश्वास जैसे मुद्दे विश्व व्यवस्था को पूर्णतः पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। भारत की ओर से माननीय पीएम की उपस्थिति न सिर्फ औपचारिकता है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और एक उभरती हुई निर्णायक शक्ति के रूप में उसकी अनिवार्य भूमिका को रेखांकित करती है।अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस संवेदनशील मोड़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सम्मेलन का बहिष्कार करना वैश्विक शक्ति संरचना और सामूहिक सहयोग की भावना पर गहरा प्रभाव डालता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि वस्तुतः 2025 का यह सम्मेलन केवल जी-20 एजेंडा का नहीं, बल्कि विश्व प्रणाली में हो रहे बड़े परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है और इस परिवर्तन के केंद्र में भारत अभूतपूर्व रूप से उभर रहा है। बहरहाल,

जोहानिसबर्ग का यह शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के लिए कूटनीतिक कसौटी है उसे अमेरिकी अनुपस्थिति की चुनौती के बीच सम्मेलन को सफलता पूर्वक संपन्न करना है। वहीं भारत के लिए यह अवसर है अपने नेतृत्व की निरंतरता दिखाने का। जब ट्रंप वैश्विक सहयोग से दूरी बना रहे हैं, तब मोदी उसी सहयोग को एक नई दिशा देने जा रहे हैं।यही विरोधाभास आज के वैश्विक परिदृश्य का सार भी है। इसलिए जोहानिसबर्ग का सम्मेलन केवल जी-20 का आयोजन नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था के पुनर्संतुलन का प्रतीक है और इस पुनर्संतुलन में भारत की भूमिका न केवल केंद्रीय है,बल्कि प्रेरक भी।

साथियों बात अगर हम जी-20 सम्मेलन में अमेरिका की अनुपस्थिति और वैश्विक बहुपक्षवाद की चुनौती को समझने की करें तो, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण पहलू है, अमेरिका का स्पष्ट बहिष्कार। ट्रंप प्रशासन द्वारा दक्षिण अफ्रीका पर लगाए गए आरोपों और ₹अमेरिका फर्स्ट₹ नीति को आगे बढ़ाते हुए इस मंच से दूरी बनाना उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें चरणबद्ध ढंग से अमेरिका अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, वैश्विक समूहों और बहुपक्षीय समझौतों से खुद को अलग कर रहा है।ट्रंप की यह नीति केवल कूटनीति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो वैश्विक सहयोग को अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध मानती है। इसके परिणामस्वरूप,जी-20 की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे हैं (1) वैश्विक आर्थिक सहयोग कमजोर हो रहा है (2) वैश्विक दक्षिण के उभार का मार्ग और स्पष्ट हो रहा है (3) अमेरिका की नैतिक और नेतृत्वकारी भूमिका कमजोर पड़ रही है,सबसे गंभीर आरोप यह है कि अमेरिका अन्य सदस्य देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे जी-20 घोषणा- पत्र पर हस्ताक्षर न करें। यदि ऐसा होता है, तो यह जी- 20 की सामूहिकता विश्वास और कूटनीतिक शक्ति को गहराई से कमजोर कर देगा। इससे 2026 में अमेरिका की जी-20 अध्यक्षता भी सवालों के घेरे में आ सकती है, क्योंकि एक नेतृत्वकर्ता की नैतिक स्थिति उसी समय मजबूत होती है जब वह सहयोग की संस्कृति में विश्वास रखता हो।

साथियों बात अगर हम 20 वें जी20 सम्मेलन के मेजबान दक्षिण अफ्रीका के सामने कूटनीतिक परीक्षा, नेतृत्व का प्रश्न खड़ा हुआ है इसको समझने की करें तो, दक्षिण अफ्रीका के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद सम्मेलन को सफल बनाना, और जी-20 के भीतर नेतृत्व की निरंतरता को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाना। परंपरा के अनुसार, सम्मेलन के समापन पर जी- 20 की अध्यक्षता का ₹बैटन₹ अगले मेज़बान देश को सौंपा जाता है।लेकिन जब अमेरिका स्वयं बैठक में मौजूद ही नहीं, तो यह प्रश्न गंभीर है कि: (1) दक्षिण अफ्रीका अमेरिकी प्रतिनिधि को बैटन सौंपे या (2) किसी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी विशेष देश को यह जिम्मेदारी दे, यह स्थिति जी-20 के इतिहास में लगभग अभूतपूर्व है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वैश्विक शक्ति-संतुलन अब पूर्ववत नहीं रहा, पश्चिमी दुनिया की केंद्रीयता कमजोर हो रही है और वैश्विक दक्षिण की भूमिका निर्णायक बनती जा रही है।दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन के माध्यम से दुनियाँ को यह संदेश देना चाहता है कि एक विकसित न होने वाला देश भी वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक विमर्शों को नेतृत्व दे सकता है।अमेरिकी दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और आंतरिक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इस सम्मेलन को सफल बनाना उसके लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी।

साथियों बात अगर हम भारत के लिए यह अवसर वैश्विक नेतृत्व का स्वर्णिम क्षण होगा इसको समझने की करें तो, अमेरिका की अनुपस्थिति ने भारत के लिए एक अप्रत्याशित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर तैयार कर दिया है।भारत पहले ही 2023 में जी- 20 की मेजबानी करके अपनी कूटनीतिक क्षमता, संवाद कौशल और वैश्विक नेतृत्व की शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। ₹एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य₹ का मंत्र दुनिया में नई सोच और नए सहयोग का आधार बन चुका है।2025 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में भारत इन कारणों से केंद्रीय भूमिका निभा सकता है (1) वैश्विक दक्षिण का स्वाभाविक नेता (2) अमेरिका और वैश्विक दक्षिण के बीच पुल का कार्य (3) वैश्विक ऊर्जा और तकनीकी बहसों में निर्णायक आवाज (4) जलवायु न्याय और विकासशील देशों की मांगों को मंच प्रदान करना (5) वैश्विक व्यापार में स्थिरता का प्रस्ताव,भारत का नेतृत्व आज इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि वह शक्ति संतुलन की राजनीति नहीं, बल्कि सहयोग और समावेशन की राजनीति को प्राथमिकता देता है।जब ट्रंप वैश्विक संस्थाओं से दूरी बना रहे हैं, तब भारत का आगे आना दुनिया को एक नए नेतृत्व मॉडल से परिचित कराता है,जहां शक्ति संवाद से आती है, न कि वर्चस्व से।

साथियों बात अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य नई विश्व व्यवस्था का पुनर्संतुलन इसको समझने की करें तो,आज का वैश्विक परिदृश्य ऐसे मोड़ पर है,जहां (1) अमेरिका और यूरोप के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है (2) रूस- यूक्रेन युद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को कमजोर कर रहा है (3) चीन और अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता वैश्विक अर्थव्यवस्था को दो ध्रुवों में विभाजित कर रही है (4) जलवायु संकट दुनिया को नई आपदाओं की ओर धकेल रहा है (5) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई भू-आर्थिक लड़ाई का केंद्र बन चुका है,ऐसे में जी-20 की भूमिका केवल आर्थिक मंच तक सीमित नहीं रही।यह आज वैश्विक प्रशासन का वैकल्पिक ढांचा बन चुका है।और ठीक इसी समय भारत की उपस्थिति, जिम्मेदारी और दृष्टिकोण वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य है।जोहान्सबर्ग का सम्मेलन वास्तव में ₹विश्वव्यवस्था का पुनर्संतुलन₹ है।ऐसा पुनर्संतुलन जिसमें,अमेरिका केंद्र में नहीं,बहुध्रुवीय नेतृत्व उभर रहा है,एशिया-अफ्रीका-लैटिन अमेरिका की आवाज़ मजबूत हो रही हैवैश्विक गणना में भारत की भूमिका सर्वाधिक प्रभावी है

साथियों बात अगर हम भारतीय पीएम का एजेंडा, तीन सत्रों क़े भारत-केन्द्रित दृष्टिकोण को समझने की करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पीएम जोहान्सबर्ग में तीनों प्रमुख सत्रों को संबोधित करेंगे, जिनके विषय न सिर्फ वैश्विक चिंताओं से जुड़े हैं बल्कि भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। (अ) समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि-भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि विकास तभी सार्थक है जब वह, समावेशी हो,सतत हो,गरीब देशों के लिए न्यायपूर्ण हो,डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग न हो।दुनियाँ आज यही सुनना चाहती है कि अगली सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी होगी और उसमें भारत जैसे देशों का क्या योगदान होगा। (ब) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन-जलवायु परिवर्तन अब 'भविष्य का संकट' नहीं, बल्कि वर्तमान की आपदा है।भारत ने क्लाइमेट जस्टिस और लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के माध्यम से एक वास्तविक समाधान दिया है।यह मॉडल विकसित देशों की अत्यधिक खपत आधारित आर्थिक प्रणाली को चुनौती देता है। (क़) न्यायपूर्ण और संतुलित भविष्य-यह वह विषय है जो वैश्विक दक्षिण की दशकों पुरानी मांग का सार है,दुनियाँ में न्यायपूर्ण संसाधन वितरण, डिजिटल समानता, तकनीकी लोकतंत्रीकरण और वैश्विक संस्थाओं में न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व। भारतीय पीएम का एजेंडा जी-20 के भविष्य को न केवल नई संरचना देता है बल्कि यह भी बताता है कि 21वीं सदी की वैश्विक सोच भारत से होकर गुजरे बिना अधूरी है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जोहान्सबर्ग 2025,विश्व नेतृत्व की नई परिभाषा-जोहान्सबर्ग जी-20 शिखर सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया के बदलते चेहरे का प्रतीक है।अमेरिका की अनुपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक नेतृत्व अब किसी एक महाशक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि कई उभरती शक्तियों के बीच साझा हो रहा है।दक्षिण अफ्रीका के सामने यह अवसर है कि वह वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूती दे और अपनी कूटनीतिक परिपक्वता दिखाए।भारत के लिए यह सम्मेलन एक ऐसी जिम्मेदारी है, जो उसे वैश्विक राजनीति के केंद्र में खड़ा करती है।ट्रंप जब वैश्विक सहयोग से दूरी बना रहे हैं, तब मोदी वैश्विक सहयोग को नए स्वरूप में आकार दे रहे हैं।यही विरोधाभास आज की विश्व व्यवस्था का सबसे बड़ा सत्य है।जोहान्सबर्ग 2025 एक निर्णायक क्षण है,जहां नया नेतृत्व उभर रहा है,नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है,और भारत विश्व राजनीति के केंद्र में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहा है।

पर्यावरण पाठशाला — "पर्यावरण अदालत : एक महागाथा"

- डॉ. अंकुर शरण

पर्यावरण पाठशाला की नई पहल "पर्यावरण अदालत" आज के समय की सबसे प्रासंगिक और चेतावनीपूर्ण कहानी है। यह महागाथा केवल कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा मानवता को भेजा गया वह संदेश है जिसे अनसुना करना हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लगा सकता है। इस कथा की शुरुआत एक रात आए स्वप्न से हुई—एक ऐसा स्वप्न, जिसने नींद खुलते ही मन में अनेक प्रश्न जगा दिए। सपने में एक भव्य अदालत थी, जहाँ इंसान कटघरे में खड़ा था और उसके सामने एक विशाल वृक्ष, नदी, पर्वत और जीव-जंतु अपनी मौन पीड़ा को शब्दों में बदलकर इंसान से जवाब मांग रहे थे। अदालत की अध्यक्षता स्वयं पर्यावरण कर रहा था, जो आज इंसान के कर्मों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य प्रतीत हो रहा था।

वृक्ष ने इंसान से पूछा कि जिसने जीवनभर उसे छाया, ऑक्सीजन और सुकून दिया, वही इंसान उसे स्वार्थवश क्यों काटता जा रहा है। वृक्ष ने अपना दर्द व्यक्त किया कि किस तरह उसकी टहनियों में कीलें ठोककर उसे विज्ञापन का स्टैंड बना दिया गया है, मानो उसकी जीवंतता का कोई मूल्य ही नहीं। छोटे पौधों की ओर से प्रश्न आया कि वे जो भविष्य की सांसें हैं, उन्हें क्यों रौंद दिया जाता है। नदी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वह जो जीवनदायिनी थी, उसे कचरा, प्लास्टिक और रसायनों का घर क्यों बना दिया गया। पर्वत और जीव-जंतु ने भी अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए बताया कि मानव ने लालच, अज्ञानता और असंयम के चलते उनके घर, उनके मार्ग और उनके अधिकार तक छीन लिए हैं।

इन सब प्रश्नों के बीच न्यायाधीश पर्यावरण की आवाज गूँजी—"इंसान! तुम्हें अधिकार तो बहुत चाहिए, पर जिम्मेदारियाँ निभाने की भावना क्यों नहीं पैदा हुई? तुमने प्रकृति से केवल लिया, पर लौटाने की कभी इच्छा नहीं की।" न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि प्रकृति कभी प्रतिशोध नहीं लेती, वह केवल चेतावनी देती है। कोरोना महामारी इसका एक उदाहरण थी, एक संकेत कि प्रकृति को संतुलित रहने की आवश्यकता है। यदि मानव अब भी नहीं सुधरा, तो आने वाले समय में आपदाएँ अधिक गंभीर और अटल हो सकती हैं—सूखा, बाढ़, जल संकट, वायु प्रदूषण, बीमारियाँ और वैश्विक तापमान वृद्धि मा न व सभ्यता को सीधी चुनौती दे सकती हैं।

इस महागाथा का निष्कर्ष यही था कि इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करे, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ समझे और पुनः संतुलन स्थापित करने का प्रयास करे। अदालत में खड़े इंसान ने अंततः वचन दिया कि वह प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानेगा। वह वृक्षों को बचाएगा, नदियों को स्वच्छ रखेगा, जीव-जंतुओं का सम्मान करेगा और पृथ्वी के साथ एक साथी की तरह व्यवहार करेगा।

पर्यावरण अदालत की यह महागाथा हमें याद दिलाती है कि हम सब इस पृथ्वी के Ecosystem Partners हैं। हम प्रकृति के बिना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ ही अस्तित्व में हैं। मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर करता है कि हम अब क्या कदम उठाते हैं। प्रकृति का संदेश स्पष्ट है—वह फिर चेतावनी देना नहीं चाहती, वह बदलाव चाहती है। और यह बदलाव आज, इसी क्षण से शुरू होना चाहिए।

आज यह सपना है,

पर इसे हक़ीक़त बनने में समय नहीं लगेगा।

इंसान है—तो इंसानियत का कर्तव्य निभाए।

पर्यावरण ने हमें बहुत कुछ दिया है,

अब मिलकर हम सब पर्यावरण को बचाएँ।

गंगा में जारी कानपुर से लापता एक्सईएन की तलाश सुराग अबतक नहीं, पत्नी से विवाद की चर्चा

सुनील बाजपेई

कानपुर। बीते 18 अक्टूबर से लापता पनकी पावर हाउस के एक्सईएन अतुल कुमार राय की खोज में पुलिस गंगा में जाल डालकर लगातार खुद बिन कर रही है लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।गत दिवस उनकी कर जाजमऊ पुल के पास मिली थी। कार से मोबाइल, पर्स और कागज भी मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या की होगी। इसी संभावना के मद्देनजर नजर आज शुक्रवार को टीमों ने करीब 10 किलोमीटर तक नदी में तलाश शुरु की। नावों से हर हिस्से को खंगाला जा रहा है। तेज धारा और गहरे स्थानों पर जाल भी डाला गया है। एक्सईएन अतुल कुमार राय को यहां एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें मिलकर खोज कर रही हैं। साथ ही पुलिस सीसी टीवी फुटेज भी देख रही है, ताकि यह पता चल सके कि अतुल पुल तक कैसे पहुंचे थे। फिलहाल परिवार ने बात करने से मना कर रहा है। बताते हैं की पत्नी से विवाद है और वह महीनों से घर नहीं लौटी हैं। इसीलिए पुलिस निजी कारणों और तनाव की भी जांच कर रही है। अलबत्ता समाचार लिखे जाने तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तलाश लगातार जारी है। पुलिस का दावा है कि स्थिति बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी।

एआई और रोबोटिक्स: एक सपना, चेतावनी और उनके बीच खड़ा भविष्य

राजेश जैन

हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में हुए तेज़ विकास से दुनिया में कुछ लोग उत्साहित हैं तो कुछ आशंकित। कुछ को लगता है कि जल्द इंसान को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ एआई, रोबोट करेंगे। दूसरी ओर अन्य लोगों का मानना है कि अनियंत्रित एआई सबकुछ नष्ट कर देगी... लेकिन दोनों तरह की सोच अतिवादी है। दरअसल, तकनीक गति देती है, दिशा नहीं। दिशा इंसान ही तय करता है-अपनी नीतियों से, संस्थाओं और समझदारी से। अगर मानव समाज अपनी तैयारी मजबूत करता है तो आने वाला समय सबसे उत्पादक और मानवीय संवेदनाओं से भरा दौर साबित हो सकता है। लेकिन अगर सुरक्षा तंत्र कमजोर रहा तो वही तकनीक सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपूर्व विकास को लेकर हाल ही में एक ओर एलन मस्क का दावा सामने आया है तो दूसरी तरफ ओपन एआई की चेतावनी आई है। एलन मस्क का दावा है कि जल्दी ही इंसान को कमाने की जरूरत नहीं रहेगी, सब काम रोबोट करेंगे। दूसरी तरफ ओपन एआई की चेतावनी है कि सुपरइंटेलीजेंस नियंत्रण से बाहर गई तो नुकसान असीम होगा। मस्क का मानना है कि 2030 तक लाखों की संख्या में ह्यूमनॉइड रोबोट उद्योगों में काम करते दिखेंगे। इससे 24×7 काम, कई गुना प्रोडक्टिविटी और हर नागरिक के लिए यूनिवर्सल हाई इनकम जनरेट होगी। एआई जब फिजिकल लेबर में बदलेगा, तब इंसान की भूमिका मूल रूप से रचनात्मक और वैकल्पिक रह जाएगी।

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इतिहास गवाह है—हर ऑटोमेशन क्रांति ने असमानता बढ़ाई है। इससे मशीनों के मालिक, कंपनियां और भी अमीर होती हैं, जबकि श्रमिकों की भूमिका घटती जाती है। इससे आय के आसमान वितरण की खाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी।

जब मशीनें खुद सोचने लगेंगी

ओपन एआई का संदेश भावनात्मक नहीं, रणनीतिक है। दरअसल, ह्यूमनॉइड रोबोट तभी उपयोगी होंगे जब उन्हें चलाने वाली एआई अत्यधिक बुद्धिमान होगी और वही सुपरइंटेलिजेंस अगर नियंत्रण से बाहर हुई, तो वही रोबोट खतरा बन जाएंगे। यानी मस्क का सपना और ओपनएआई की चेतावनी, दोनों एक ही हाईवे के दो अलग साइनबोर्ड हैं -एक विकास की दिशा दिखाता है, दूसरा खतरे की चेतावनी देता है।

खतरा यह कि नियंत्रण तंत्र कमजोर हुआ तो एआई खुद लक्ष्य चुन सकती है। ऐसे में साइबर और बायो-रिस्क नए रूप ले सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ एआई तेज हो रही है, वाली कहानी नहीं, यह एआई इंसानी ढांचे को पार करने वाली चेतावनी है।

मस्क बनाम ओपन एआई?

ह्यूमनॉइड रोबोट तभी उपयोगी होंगे जब उन्हें चलाने वाली एआई अत्यधिक बुद्धिमान होगी और वही सुपरइंटेलिजेंस अगर नियंत्रण से बाहर हुई, तो वही रोबोट खतरा बन जाएंगे। यानी मस्क का सपना और ओपनएआई की चेतावनी, दोनों एक ही हाईवे के दो अलग साइनबोर्ड हैं। इनमें एक विकास की दिशा दिखाता है, दूसरा खतरे की चेतावनी देता है।

चार संभावित दिशाएं, जिस ओर भविष्य की दुनिया मुड़ सकती है

1. रोबोटिक समृद्धि का मॉडल: उत्पादन में उछाल, शिक्षा-स्वास्थ्य में क्रांति और हर नागरिक के लिए सुरक्षित आय।
2. असमानता का अतिवादी मॉडल: कुछ कंपनियों के पास सारा नियंत्रण, समाज में गहरी आर्थिक खाई और निराशा।
3. अनियंत्रित सुपरइंटेलिजेंस: ऐसी मशीनें जो इंसान की समझ से परे फैसले लें और नियंत्रण खत्म हो जाए।
4. संतुलित सह-अस्तित्व: सख्त नियम, पारदर्शी एल्गोरिद्म और ग्लोबल निगरानी से नियंत्रित तकनीकी विकास।

भविष्य कौन-सा रास्ता चुनता है, यह हमारी नीतियों, राजनीति और सामाजिक तैयारी पर निर्भर करेगा। बहरहाल, समाज के ढांचे में बदलाव तय है। घरों में बुजुर्गों से लेकर बच्चों की देखभाल तक में रोबोट मुख्य भूमिका निभाएंगे। हर बच्चे को उसके अनुकूल शिक्षा मिलेगी। स्कूलों में एक ही क्लासरूम में 40 बच्चे होंगे, पर 40 अलग-अलग पाठ्यक्रम चलेंगे। रूटीन जॉब्स खत्म होंगे लेकिन 'ह्यूमन-लेयर' वाली नौकरियां उभरेंगी—क्यूरेटर, फैसिलिटेटर, क्रिएटर।

अर्थव्यवस्था में टैक्स मॉडल बदलेगा। जैसे-रोबोट टैक्स लगेगा, नई वेलफेयर योजनाएं आएंगी। साथ ही दुनिया को अगले दशक में ग्लोबल एआई रेगुलेशन, एल्गोरिदम पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा के नए मानक और एआई गलती से निपटने की जरूरत होगी।

दिशा इंसान तय करेगा, तकनीक नहीं

तकनीक का भविष्य न तो पूरी तरह सपना है, न पूरा खतरा। यह इंसान की समझदारी, संवेदना और दूरदर्शिता की परीक्षा है। अगर हमने सही दिशा तय की, तो आने वाला दशक इंसान और तकनीक के सह-अस्तित्व का सबसे सुंदर युग बन सकता है वरना वही तकनीक, जो आज हमारी मददगार है, कल हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है।

ऑपरेशन हॉक: साइबर ठगों और ऑनलाइन वित्तीय अपराध नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के संगठित नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी, सुव्यवस्थित और रणनीतिक अभियान चलाते हुए "ऑपरेशन CyHawk" को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। पुलिस आयुक्त, श्री सतीश गोल्छा, आईपीएस के नेतृत्व में तैयार इस ऑपरेशन ने साइबर अपराध से निपटने की पारंपरिक प्रतिक्रिया-आधारित प्रक्रिया को बदलते हुए, प्रो-एक्टिव, इंटेलिजेंस-ड्रिवन और ठोस कार्रवाई-आधारित मॉडल की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह ऑपरेशन उन साइबर नेटवर्कों को जड़ से कमजोर करने के उद्देश्य से संचालित किया गया, जो फर्जी लेनदेन, म्यूल बैंक खातों, नकदी निकालने वाले एजेंटों और अवैध कॉल सेंटरों के माध्यम से देशभर के नागरिकों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाते रहे हैं।

इस अभियान को शुरू करने से पहले लगभग एक माह तक I4C, गृहमंत्रालय के साथ मिलकर विस्तृत खुफिया विश्लेषण किया गया। इस दौरान साइबर हॉटस्पॉट्स की पहचान, संदिग्ध मोबाइल नंबरों और म्यूल खातों की जांच, डिजिटल फुटप्रिंट का अध्ययन, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण और देशभर से प्राप्त साइबर शिकायतों की कड़ियों को जोड़ने का बेहद व्यापक और सटीक कार्य किया गया। इन गहन इनपुट्स के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उन आर्थिक और डिजिटल चैनलों पर निशाना साधा, जिन पर साइबर ठगी का विशाल नेटवर्क टिका हुआ था।

ऑपरेशन CyHawk का नेतृत्व ज़मीनी स्तर पर विशेष पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था ज़ोन-II, श्री मधुप तिवारी, और विशेष पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेल, श्री अनिल शुक्ला के मार्गदर्शन में किया गया। संयुक्त आयुक्त, IFSO, श्री रजनीश गुप्ता और संयुक्त आयुक्त दक्षिण रेंज, श्री एस.के. जैन के समन्वयन में दिल्ली के सभी जिलों में एक साथ कार्रवाई की गई। इस सघन और व्यापक अभियान ने राजधानी में संचालित कई संगठित साइबर सिंडिकेट्स की संचालन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया और धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्कों को कमजोर कर दिया।

पूरे दिल्ली में एक साथ की गई इस कार्रवाई में 4467 व्यक्तियों को पूछताछ और सत्यापन हेतु उठाया गया, जिनमें से 877 आरोपियों को पुख्ता डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया गया। 509 व्यक्तियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान 360 नए एफआईआर दर्ज किए गए, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा और अधिक मजबूत हुआ। इसके अलावा, लंबित 160 साइबर मामलों में भी कई आरोपी पकड़े गए, जिससे पूर्व में चल रही जांचों को बड़ी सफलता मिली। लगभग 3777 NCRP शिकायतों को म्यूल खातों और संदिग्ध मोबाइल नेटवर्कों से जोड़ने में सफलता मिली, जिससे जांच को नई दिशा और गहराई मिली। देशभर में दर्ज साइबर शिकायतों में बताए गए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी राशि को कई म्यूल बैंक खातों और साइबर अपराधियों के खातों के माध्यम से जुड़े होने की पुष्टि की गई। इसी के साथ, राजधानी में सक्रिय कई अवैध कॉल सेंटरों को बंद कराया गया, जो नौकरी के नाम पर, कस्टमर केयर बनकर, टेक-सपोर्ट सहायता के बहाने या निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को ठगने में लिप्त थे। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सिम कार्ड, बैंकिंग कार्ड, रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिनका विशेषज्ञों द्वारा गहन फॉरेंसिक विश्लेषण जारी है।

इस व्यापक अभियान से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय जानकारियों के आधार पर आने वाले दिनों में कई और कड़ियों पर कार्रवाई की संभावना है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई ने राजधानी में सक्रिय कई बड़े साइबर नेटवर्कों की रीढ़ को तोड़ दिया है और उनकी संचालन क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। कई महत्वपूर्ण सुराग सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई अन्य राज्यों और इंडस्ट्रीज तक भी विस्तारित की जाएगी।

पुलिस आयुक्त, श्री सतीश गोल्छा, आईपीएस ने कहा कि "ऑपरेशन CyHawk दिल्ली पुलिस की इस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि साइबर अपराध को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने साइबर ठगों के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त कर यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली उनके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं है। यह ऑपरेशन अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारा संकल्प है— साइबर सुरक्षित दिल्ली और साइबर सशक्त भारत।"

दिल्ली पुलिस ने I4C, गृहमंत्रालय, सभी साइबर विशेषज्ञ टीमों, बैंकिंग संस्थानों, टेलीकॉम भागीदारों और अन्य सहयोगी एजेंसियों का धन्यवाद किया है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया कि इसी प्रकार की तकनीक-आधारित, लक्षित और खुफिया-नेतृत्व वाली कार्रवाइयाँ नियमित रूप से जारी रहेंगी, जिससे साइबर अपराधियों को निरंतर दबाव में रखा जा सके।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे साइबर सतर्कता अपनाएं, डिजिटल सावधानियां बरतें और किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश, लिंक या ऑफर के झांसे में न आएं। "स्टॉप–थिंक–एक्ट" डिजिटल सुरक्षा मंत्र का पालन करें, बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें, स्क्रीन-शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड न करें, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण सक्षम रखें और किसी भी साइबर फ्रॉड की कोशिश की रिपोर्ट "संचार साथी" ऐप या NCRP पोर्टल पर दर्ज करें। नियमित अपडेट के लिए नागरिक @CyberDost और @DelhiPolice के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं।

साइबर अपराध से प्रभावित व्यक्ति दिल्ली के किसी भी थाने में स्थापित इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। समय पर शिकायत दर्ज करवाना धोखाधड़ी की गई राशि को रोकने और अपराधियों की गिरफ्तारी की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है।

मालिकों की बजाय सरकारी और गैर-सरकारी ज़मीनें ठेके पर लेकर खेती करने वाले प्रभावित किसानों को ही फसलों के नुकसान का मुआवज़ा मिलेगा — धालीवाल

पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गए 14 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग को केंद्र सरकार जांच-पड़ताल के बहाने अभी भी लटकाए बैठी है — धालीवाल

श्री धालीवाल ने 47 गांवों के प्रभावित 2355 किसानों में 9.55 करोड़ रुपये की राशि के प्रमाण पत्र बांटकर राहत पहुंचाई

अमृतसर/अजनाला, 21 नवंबर (साहिल बेरी) — आज यहां एसडीएम अजनाला श्री रविंदर सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता में बाढ़-पीड़ित किसानों की नुकसान हुई फसलों के मुआवज़े की मंज़ूर हुई राशि के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दो-पड़ाव वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हलका विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इलाके के कुल 47 गांवों के 2355 प्रभावित किसानों को कुल 9.55 करोड़ रुपये मुआवज़े की मंज़ूर राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री धालीवाल ने निजी और सरकारी ज़मीनों को ठेके पर लेकर खेती करने वाले किसानों की शंकाएँ दूर करते हुए स्पष्ट घोषणा की कि निजी ज़मीनें मालिकों से ठेके पर लेकर खेती करने वाले, जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन्हें ही फसलों के नुकसान का मुआवज़ा दिया जाएगा, जबकि ठेके पर दी गई ज़मीनों के मालिकों को मुआवज़े का कोई हक़ प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह सरकारी ज़मीनों पर बटाई/ठेके पर खेती कर रहे किसानों को मुआवज़ा देने का दृढ़ और किसान-हितैषी फ़ैसला पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने ले लिया है।

श्री धालीवाल ने यह भी दोहराया कि प्रभावित किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवज़ा 30 नवंबर तक हर हाल में वितरित कर दिया जाएगा, जबकि अगले चरण में नुकसान हुए घरों और अन्य नुकसान के लिए भी मुआवज़ा

राशि बांटने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंजाब मान सरकार ने कदम उठा लिए हैं।

श्री धालीवाल ने केंद्र सरकार को पंजाब और पंजाबी विरोधी करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज में से पंजाब को एक नया पैसा तक नहीं दिया गया और न ही अपने वादे के अनुसार फसलों के नुकसान का मुआवज़ा केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों के खातों में सीधे भेजा गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमले जारी रखते हुए कहा कि पंजाब मान सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर अगस्त महीने के अंत और सितंबर महीने के पहले पखवाड़े में आई बाढ़ के दौरान फसलों, घरों, पशुओं और अन्य बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान के लिए करीब 14 हज़ार करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज भेजा गया था। इस पैकेज में दर्ज नुकसानी मदों (घर, पशु एवं अन्य बुनियादी ढांचा) की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा दो बार अपनी निगरानी में केंद्रीय टीमें पंजाब भेजी गईं।

करीब तीन महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक भी पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने का मामला लटकाया जा रहा है। केंद्रीय टीम द्वारा 35 हज़ार नुकसान हुए घरों में से अभी तक केवल 30 हज़ार घरों की ही जांच पूरी की जा सकी है। जबकि किसानों के साथ कथित धोखा करते हुए बाढ़ के कारण बदरंग हुई धान की फसल की सरकारी खरीद में नमी, बदरंग दानों आदि मामलों में किसानों को कोई राहत नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि बाढ़-पीड़ित किसानों सहित आम लोगों के साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय पैकेज देने की जगह किए जा रहे सौतेले व्यवहार पर पंजाब भाजपा कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रही है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा को मानो साँप सूँघ गया हो।

27 नवंबर को लगाया जाएगा जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण कैंप — मुख्य कृषि अधिकारी

अमृतसर, 21 नवंबर (साहिल बेरी)

मुख्य कृषि अधिकारी श्री गुरसाहिब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से रबी 2025 की फसलों की काश्त संबंधी तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह कैंप 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दाना मंडी गहरी, जी.टी. रोड, जंडियाला गुरु में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. होंगे, जो इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि इस कैंप में किसानों को रबी फसलों संबंधी नवीनतम एवं तकनीकी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी और स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस प्रशिक्षण कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

अमृतसर नगर निगम में 60 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

अमृतसर, 21 नवंबर (साहिल बेरी)

मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने मेयर सरदार जतिंदर सिंह भाटिया और कमिश्नर कॉरपोरेशन श्री बिक्रमजीत सिंह के साथ अमृतसर नगर निगम में 60 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

इस मौके पर इंटक यूनियन के प्रधान सुरिंदर सोनू ने अपनी यूनियन के सदस्यों के साथ मिलकर मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह का खुले दिल से गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। इसके उपरांत उन्होंने निगम दफ़्तर में नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अमृतसर नगर निगम ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू की गई रोजगार मुहिम और पंजाब को दोबारा मज़बूत खड़ा करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति से एक ओर जहां इन परिवारों को रोजगार मिला है, वहीं दूसरी ओर ये शहर की सफाई व्यवस्था और अन्य सेवाओं में अपना योगदान देंगे।

मंत्री ने बताया कि आज सुबह वे मेयर, कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ शहर के मुख्य बाज़ारों का दौरा कर सफाई प्रबंधों का जायज़ा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं और आगामी दिनों में कूड़ा उठाने से जुड़ी सभी कमियों को दूर कर अमृतसर शहर को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह समस्या पिछली कंपनी 'अवाडा' द्वारा काम छोड़ देने के कारण उत्पन्न हुई थी। सरकार ने कंपनी को काम जारी रखने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कंपनी इच्छुक नहीं थी, जिसके चलते उनका टेंडर रद्द कर नया टेंडर आवंटित किया गया। मंत्री ने बताया कि नई कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। काम नया होने के कारण दो-एक कमियां महसूस हुई हैं, जिन्हें सरकार कंपनी के साथ मिलकर दूर कर रही है ताकि अमृतसर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आ सके।

समाजसेविका राजकुमारी देवी द्वारा रणजीत नगर में बाटे मास्क

नवदीप सिंह

रणजीत नगर के अंदर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य को हो रहे प्रदूषण से नुकसान को कम करने के लिए वितरण किए 200 लोगों मास्क। राजकुमारी देवी समाजसेविका की तरफ से लोगों को प्रेरित किया गया कि आप जब भी सुबह शाम बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले जिससे आपको प्रदूषण का असर कम हो और थोड़ी ऑक्सीजन मिल सके। आप हमेशा स्वस्थ रहें यह जागरूकता अपनी टीम के साथ राजकुमारी देवी ने पब्लिक को दी।

झारखंड , बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई

झारखंड में 18 तो कुल 40 जगह पर एक साथ छापेमारी , सरकार को सैकड़ों करोड़ का नुक़सान का मामला

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला माफिया के खिलाफ 40 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापामारी की है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 परिसरों में अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण मामले के संबंध में तलाशी ले रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, नरेंद्र खरका, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल और अन्य के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। बंगाल में रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश एवं जेवरात बरामद हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी झारखंड में 18 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ये छापामारी कोयला चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मामलों से जुड़े हैं, जिसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता शामिल हैं। यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े मामलों में की जा रही है। जहां आगे जांच की कड़ी मे बड़ी मछलियां भी फंसने की संभावना है

छत्तीसगढ़ एंटी नक्सल आप्रेशन में झारखंड के कमांडेंट को मिला सर्वश्रेष्ठ बटालियन ट्रॉफी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, नक्सली आप्रेशन में झारखंड के गढ़वा जिला के निवासी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बीपी) के कमांडेंट विवेक कुमार पांडेय को छत्तीसगढ़ में असाधारण ऑपरेशनल सफलता और क्षेत्र में व्यापक सामुदायिक सेवा के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ नक्सल विरोधी बटालियन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है. विवेक पांडेय छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शुमार मानपुर के 27वीं बटालियन में तैनात हैं. उनको यह सम्मान इंडो-तिब्बत के डीजी प्रवीण कुमार ने वार्षिक बल स्थापना दिवस महानिदेशक परेड के दौरान जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में प्रदान किया. महानिदेशक ने यूनिट के उत्कृष्ट अभियान कौशल और प्रदर्शन की सराहना की है.

गढ़वा जिला के मझिआंव थाना क्षेत्र के ऊंचरी ग्राम निवासी कमांडेंट विवेक कुमार पांडेय, स्वर्गीय रामनाथ पांडेय के बेटे हैं. पत्रकारिता और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. साल 2003 से आई टी बीपी में सेवारत हैं. इस दौरान वह जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ एवं केरल में तैनात रहे हैं.

प्रारंभिक शिक्षा सुदूर ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा रांची कॉलेज और इतिहास विभाग, रांची विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई है. पहले एसएससी और फिर यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा पास कर अधिकारी बने. फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उनकी यह उपलब्धि न केवल आई टी बीपी के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है. कमांडेंट विवेक को साल 2007 में असम में उल्फा के विरुद्ध बहादुरी अभियानों के लिए सेनाध्यक्ष के प्रशंसा डिस्क से भी सम्मानित किया जा चुका है.

मोहला-मानपुर के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में 2023 में कमांडेंट के रूप में तैनाती के बाद, कमांडेंट विवेक कुमार पांडेय ने गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) और कांकेर (छत्तीसगढ़) की सीमाओं के निकट कई बड़े रणनीतिक अभियान चलाए गए. उनकी बटालियन ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसे केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक नक्सल आतंक को समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

आर्मी ड्राइवर्स के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष रोड सेफ्टी जागरूकता सत्र का आयोजन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा राजधानी में सड़क अनुशासन और सुरक्षित यातायात व्यवहार को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के तहत आज टीपीटी आर्मी मुख्यालय में सेना के ड्राइवर्स के लिए विशेष रोड सेफ्टी अवेयरनेस सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक मुख्यालय) श्री सत्यवीर कटारा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस पहल का उद्देश्य सेना के उन कर्मियों में सुरक्षित ड्राइविंग आदतों को और अधिक मजबूत करना है, जो रोज़ाना भारी एवं महत्वपूर्ण सैन्य वाहनों का संचालन करते हुए दिल्ली की सड़कों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस जागरूकता कार्यक्रम में कुल 55 आर्मी ड्राइवर्स और 03 अधिकारी शामिल हुए। सत्र के दौरान प्रशिक्षकों ने सुरक्षित ड्राइविंग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी, जिनमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नियंत्रित गति रखना, सीट बेल्ट का नियमित उपयोग, थकान से बचने के लिए सतर्क रहना, और भारी सैन्य वाहनों को भीड़भाड़ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक चलाने के तरीके शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि सेना के कर्मियों में स्वाभाविक रूप से अनुशासन, सतर्कता और जिम्मेदारी का भाव होता है, जो उन्हें अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श बनाता है। उनकी जिम्मेदार ड्राइविंग न केवल दुर्घटनाओं को कम करती है, बल्कि पूरे यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में अहम योगदान देती है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ऐसे रोड सेफ्टी कार्यक्रम बड़े और भारी वाहनों को संचालित करने वाले ड्राइवर्स के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि यह उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति और अधिक जागरूक तथा संवेदनशील बनाते हैं। ट्रैफिक पुलिस भविष्य में भी इसी प्रकार के जागरूकता अभियानों का विस्तार विभिन्न संस्थानों, स्कूलों, परिवहन क्षेत्रों और आम नागरिकों तक करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामूहिक प्रयासों और निरंतर जागरूकता के माध्यम से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का लक्ष्य एक सुरक्षित, स्मार्ट और अनुशासित दिल्ली का निर्माण करना है।

ओडिशा नॉन-फॉर्मल टीचर्स एसोसिएशन के वर्कर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : भुवनेश्वर के गोदावरी साहित्य संसद हॉल में राज्य के सभी जिलों के नॉन-फॉर्मल टीचर्स एसोसिएशन के सभी मुख्य वर्कर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें चीफ वाइस प्रेसिडेंट सोमनाथ मोहंती, जनरल एडिटर नरहरि प्रधान, ट्रेजर साधु प्रधान, मनोरमा बेहरा लीगल एडवाइजर, बिरंचिनारायण सतपथी- एडवाइजर और एडिटर के साथ चाइना स्वैन मौजूद थे। तत्कालीन सरकार को बधाई दी गई और आगे की एक्टिविटीज़ पर चर्चा की गई। पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को लेटर लिखने के लिए चीफ मिनिस्टर, पब्लिक एजुकेशन मिनिस्टर और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सूर्य रावल को धन्यवाद दिया।

राज्य कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, ओडिशा में 5 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: राज्य कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 9 डिपार्टमेंट के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी। स्टील और माइंस डिपार्टमेंट के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फाइनेंस, IT समेत कई डिपार्टमेंट के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने SC/ST स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने को मंजूरी दी। ओडिशा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। कैपेसिटी सेंटर के लिए हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। वॉटर पॉल्यूशन रूल्स में बदलाव के प्रपोज़ल को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में राज्य कैबिनेट की एक ज़रूरी मीटिंग हुई। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएगी। यह स्कॉलरशिप आम स्टूडेंट्स को दी जा रही है। अब 11 हज़ार रुपये की जगह मेल स्टूडेंट्स को 16 हज़ार रुपये और फीमेल स्टूडेंट्स को 17 हज़ार रुपये मिलेंगे।

राज्य में रेत और पत्थर माइनिंग के लिए कोई ऑक्शन नहीं होगा। अब लीज़ ई-लॉटरी से दी जाएंगी। कैबिनेट ने माइनर मिनरल रिसोर्स के एलोकेशन के लिए इस नए रूल को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले से माइनर मिनरल रिसोर्स के एलोकेशन और एफिशिएंसी में तेज़ी लाने, सप्लाई और डिमांड के बीच के गैप को कम करने और माइनर मिनरल्स को सस्ते दामों पर देने में मदद मिलेगी। ओडिशा में यूनिफ़ॉर्म्ड सर्विसेज़ में रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए एक कमीशन होगा। यूनिफ़ॉर्म्ड सर्विसेज़ पर्सनेल सिलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। यह कमीशन पुलिस, एक्साइज़ और फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यूनिफ़ॉर्म्ड सर्विसेज़ में रिक्रूटमेंट के लिए जांच करेगा।

ओडिशा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसमें करीब 1 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। इसमें ओडिशा में 5 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब बनाए जाएंगे। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप, बरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर में हब बनाने का टारगेट है।

विधानसभा भवन में मनाई गई डॉ. हरेकृष्ण महताब की जयंती

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: नवउत्कल के निर्माता उत्कल केशरी डॉ. हरेकृष्ण महताब की बहुमुखी प्रतिभा और योगदान ओडिशा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनके सशक्त नेतृत्व और निस्वार्थ जीवन ने ओडिशा को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई और लोगों के मन में एक नई क्रांति लाई। ओडिशा की मिट्टी, पानी और हवा से अटूट रूप से जुड़े महताब ने पूरे राज्य में एक चेतनापूर्ण माहौल बनाया। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर वे आधी सदी से भी अधिक समय तक ओडिशा और भारत की राजनीति पर छाए रहे। स्वतंत्रता संग्राम के अलावा साहित्य और संस्कृति की प्रगति में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने सुप्त ओड़िया राष्ट्र की आत्मा में अभूतपूर्व जागृति पैदा की।

आज डॉ. हरेकृष्ण महताब की जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाढ़ी, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री श्रीमती. पार्वती परिदा, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया, स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद गांडेय, सरकारी दल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री सरोज प्रधान, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री गोविंद चंद्र दास, विधायक श्री बाबू सिंह एवं श्री प्रताप चंद्र प्रधान, उत्कल सम्मेलन के कार्यकर्ता, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत शर्मा, विधानसभा सचिव श्री सत्यव्रत राउत उपस्थित थे और विधानसभा परिसर में डॉ. महताब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा के शोध प्रकोष्ठ द्वारा डॉ. हरेकृष्ण महताब की जीवनी पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान शाश्वती सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सुश्री रोजलिन साहू ने किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023